mediaauditornews@gmail.com mediaauditor Epaperdainikmediaauditor.in mediaauditor वर्ष-28 अंक-342 | पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

रीवा

13 दिसंबर 2024 शुक्रवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

रीवा, सतना से एक साथ प्रकाशित

जो रूट बादशाहत...

@ पेज 7

18 साल के गुकेश शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन

कोलकता (एजेंसी)। 18 साल के भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में गुरुवार को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन को 7.5-6.5 से

● सबसे कम उम्र में खिताब जीता, चीनी खिलाड़ी को 14वें गेम में हराया

फाइनल में हराया। इतनी कम उम्र में खिताब जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले प्लेयर बने हैं। इससे पहले 1985 में रूस के गैरी कैस्परोव ने 22 साल की उम्र में यह खिताब जीता था। गुकेश ने चीनी खिलाड़ी को 14वें गेम में हराकर यह टाइटल जीता। 25 नवंबर को चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हुआ

था, 11 दिसंबर तक दोनों के बीच 13 गेम खेले गए। स्कोर यहां 6.5-6.5 से बराबर था। गुकेश ने आज 14वां गेम जीता और एक पॉइंट की बढ़त लेकर स्कोर 7.5-6.5 कर दिया। गुकेश चेस के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले भारत के दूसरे ही प्लेयर बने। 2012 में विश्वनाथन आनंद चेस चैंपियन बने थे। गुकेश ने 17 साल की उम्र में स्नद्बष्ठश्च कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट भी जीता था। तब वह इस खिताब को जीतने वाले भी सबसे युवा प्लेयर बन गए थे। रविवार तक 11 गेम के बाद गुकेश 6-5 से आगे थे। 11 में से 8 गेम ड्रॉ रहे थे, जबकि 2 में गुकेश और 1 में लिरेन को जीत मिली थी। लिरेन ने फिर वापसी की और 12वां गेम जीत लिया और स्कोर फिर बराबर कर दिया। बुधवार को 13वीं बाजी में 68 चाल के बाद गुकेश को गेम ड्रॉ खेलना पड़ा था। तब स्कोर 6.5-6.5 से बराबरी पर था। गुकेश ने तीसरा, 11वां और 14वां गेम जीता। वहीं लिरेन ने पहला और 12वां गेम जीता। बाकी गेम ड्रॉ रहे। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के 138 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एशिया के 2 खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन के खिताब के लिए आमने-सामने थे। चैंपियन बनने वाले गुकेश को 20.86 करोड़ रुपए (2.5 मिलियन यूएस डॉलर) मिलेंगे।

गुकेश डी का पूरा नाम डोम्माराजू गुकेश है। वह चेन्नई के रहने वाले हैं। गुकेश का जन्म चेन्नई में 7 मई 2006 को हुआ था। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। उन्हें शुरू में भास्कर नागैया ने कोचिंग दी थी। नागैया इंटरनेशनल चेस खिलाड़ी रहे हैं और चेन्नई में चेस के होम ट्यूटर हैं। इसके बाद विश्वनाथन आनंद ने गुकेश को खेल की जानकारी देने के साथ कोचिंग दी।

संक्षिप्त समाचार

रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी भयानक जंग, खतरे में लोग

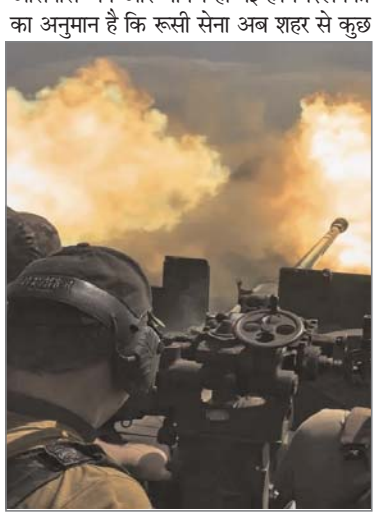

कीव (एजेंसी)। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस बीच यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ने कहा है कि रूस के लगातार आक्रमण के बाद पूर्वी यूक्रेन के प्रमुख शहर पोक्रोवस्क के आसपास जंग और भीषण हो गई है। विश्लेषकों का अनुमान है कि रूसी सेना अब शहर से कुछ

ही किलोमीटर की दूरी पर है। जनरल स्टाफ ने बृहस्पतिवार को युद्धक्षेत्र रिपोर्ट में कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने पिछले 24 घंटों में पोक्रोवस्क के आसपास सुरक्षा बलों पर हमला करने के रूस के लगभग 40 प्रयासों को विफल कर दिया। यूक्रेनी सेना प्रमुख जनरल ओलेक्सांद्र सिरस्की ने बुधवार देर रात फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, ÷कब्जा करने वाले रूसी अपनी सारी उपलब्ध ताकतें आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे सैनिकों की सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।÷ उन्होंने कहा कि उनकी सेना संख्या में कम है। रूसी सेनाएं यूक्रेन की सुरक्षा को ग्लाइड बमों के साथ ध्वस्त करने की कोशिश कर रही हैं।

सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बढ़ी मुश्किलें

संभल (एजेंसी)। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वर्क के मकान पर बुलडोजर एक्शन और भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है। बिना नक्शा पास कराए मकान के निर्माण को लेकर उन्हें नोटिस सौंपा गया है। प्रशासन की ओर से धारा 10 रेगुलेशन,ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत यह नोटिस उन्हें सौंपा गया है। सपा सांसद बर्क से इस पूरे मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। नोटिस में बर्क को अवैध निर्माण के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। मकान का निर्माण नहीं रोकने पर 10 हजार रुपये का जुर्माने के साथ ही हर रोज के हिसाब से

500 रुपया और जेल की सजा भी हो सकती है। इसके साथ ही धवस्तीकरण की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि पिछले दो साल से वर्क के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। सपा सांसद बर्क का निर्माणाधीन मकान नख़ासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय में बन रहा है। प्रशासन की ओर से यह नोटिस ऐसे वक्त पर दी गई है जब एक दिन पहले बुधवार को संभल में बुलडोजर गरजा था। सांसद बर्क ने इसका विरोध किया था।

लंदन की सड़ों पर संसद घेरने ट्रैक्टर से पहुंचे किसान

लंदन (एजेंसी)। भारत में किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी लेकिन अब एक और देश में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। लंदन की चमचमाती और शनदार सड़कों पर बुधवार को अचानक ट्रैक्टर दौड़ने लगे। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों को देख लोग हैरान रह गए। आखिरकार कुछ देर बात पता चल कि यह कोई ट्रैक्टर रेस नहीं बल्कि परेशान किसान हैं जो कृषि परिवारों को %विरासत कर% (इनहेरिटेंस टैक्स) में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। सेंट्रल लंदन की सड़कों पर किसानों ने विरोध के दौरान ट्रैक्टर मार्च किया, रास्तों को बंद कर दिया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसान परिवारों को इनहेरिटेंस टैक्स में शामिल ना किया जाए। किसान इस टैक्स से छूट की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इससे पारिवारिक खेत नष्ट हो जाएंगे, खाद्य उत्पादन कम हो जाएगा। सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से किसानों ने संसद भवन मार्ग को भी ट्रैक्टरों को ब्लॉक कर था। संसद के बाहर भी किसान तख्तियों के साथ खड़े नजर आए। इन तख्तियों पर लिखा था, ÷किसान नहीं, तो भोजन नहीं, भविष्य नहीं।÷

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

प्रताड़ना को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कह सकते

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति पर किसी की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोष तभी लगाया जा सकता है, जब इसका पुख्ता सबूत हो। सिर्फ प्रताड़ना का आरोप इसके लिए काफी नहीं है। यह टिप्पणी विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ ने 10 दिसंबर को गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले पर सुनवाई के दौरान दी।

दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने एक महिला के उत्पीड़न और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में उसके पति और ससुराल वालों को बरी करने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए उन्हें महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब बेंगलुरु में 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला चर्चा में है। अतुल ने 24 पेज के

सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और उसके घरवालों पर उसे प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। इसके आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है।

गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2021 में यह केस ढ्ढक्क की धारा 498 (विवाहित महिला के साथ क्रूरता करना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दर्ज किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 306 के तहत दोषी पाए जाने के लिए व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने की नीयत के पुख्ता सबूत होना जरूरी है। आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाए जाने का दोषी साबित करने के लिए सिर्फ प्रताड़ना काफी नहीं है।

राज्यसभा के अध्यक्ष ने किया शक्ति का दुरुपयोग

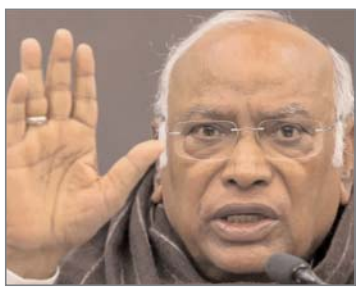

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा के अध्यक्ष व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। विपक्ष ने जगदीप धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट

में उन्होंने बताया है कि कैसे राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने शक्ति का दुरुपयोग किया और उन्होंने पक्षपात किया। इसके लिए मल्लिकार्जुन खरगे ने 10 प्वाइंट्स भी शेयर किए हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने लिखा, %लोकतंत्र हमेशा दो पहियों पर चलता है। एक पहिया है सत्तापक्ष और दूसरा विपक्ष। दोनों की जरूरत होती है। सांसदों के विचारों को तो देश तब ही सुनता है जब हाउस चलता है।

नितिन गडकरी बोले- मैं अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं

सड़क हादसों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिए मानवीय व्यवहार में बदलाव लाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने पहली बार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का कार्यभार संभाला था, तब उन्होंने दुर्घटनाओं में 50 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य रखा था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नितिन गडकरी ने कहा, दुर्घटनाओं की संख्या में कमी की बात तो भूल ही जाइए, मुझे यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है कि इसमें वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जब मैं जब मैं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने जाता हूं, जहां सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा होती है, तो मैं अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि चीजों को

बेहतर बनाने के लिए भारत में मानवीय व्यवहार को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा और कानून के शासन का सम्मान करना होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 1.78 लाख लोगों की जान जाती है और इनमे से 60 फीसदी पीड़ित 18-34 वर्ष की आयु के होते हैं।

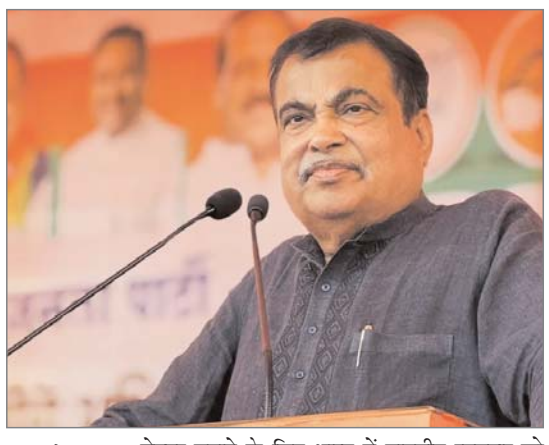

हाथरस के पीड़ित परिवार से फिर मिले राहुल

इसे लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर बयान दिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज एक बार फिर हाथरस पहुंचे। बता दें कि यहां हाथरस के पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने फिर से मुलाकात की। इसे लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर बयान दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ÷आज हाथरस जाकर 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिवार से मिला। मुलाक़ात के दौरान उन्होंने जो बातें बताई उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है। उनके साथ क्रिमिनल्स के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वे स्वतंत्र रूप से कहीं आ-जा नहीं सकते हैं - उन्हें हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। राहुल गांधी ने एक्स पर आगे लिखा, भाजपा सरकार ने उनसे जो वादे किए थे, वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। न तो सरकारी नौकरी दी गई है और न ही उन्हें किसी दूसरी जगह घर देकर शिफ्ट करने का वादा पूरा किया गया है। पीड़ित परिवार को न्याय देने के बजाय, सरकार उन पर तरह-तरह से अत्याचार कर रही है। दूसरी तरफ़ आरोपी

खुलेआम घूम रहे हैं। इस परिवार की हताशा और निराशा भाजपा द्वारा दलितों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार की सच्चाई को दिखाते हैं। लेकिन हम इस परिवार को यूं ही इनके हाल पर रहने को मजबूर नहीं होने देंगे। इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे।

बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा में इन दिनों खूब बहस देखने को मिल रही है। इस दौरान विपक्षी दलों द्वारा राज्यसभा के अध्यक्ष व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष का आरोप है कि जगदीप धनखड़ पक्षपात करते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। बता दें कि इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 10 प्वाइंट्स शेयर किए हैं और उन्होंने बताया है कि कैसे राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और पक्षपात किया जा रहा है।

चोट करनी है तो दिमाग पर कीजिए, दिल पर नहीं

राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान धनखड़ ने कहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा में पिछले कुछ दिनों से जारी हंगामे और विपक्षी दलों द्वारा सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के प्रस्ताव के नोटिस के बीच गुरुवार को उन्होंने विपक्षी दलों को रिश्तों की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि चोट करनी है तो दिमाग पर कीजिए, दिल पर नहीं। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही धनखड़ ने वरिष्ठ सदस्य शरद पवार और बीजेपी के हर्ष महाजन के जन्मदिन का जिक्र किया और उन्हें सदन की ओर से बधाई दी। जब वे महाजन के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का जिक्र कर रहे थे, तो विपक्षी सदस्य ने उनके कांग्रेस से रिश्तों का जिक्र किया, जिस पर सभापति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी।

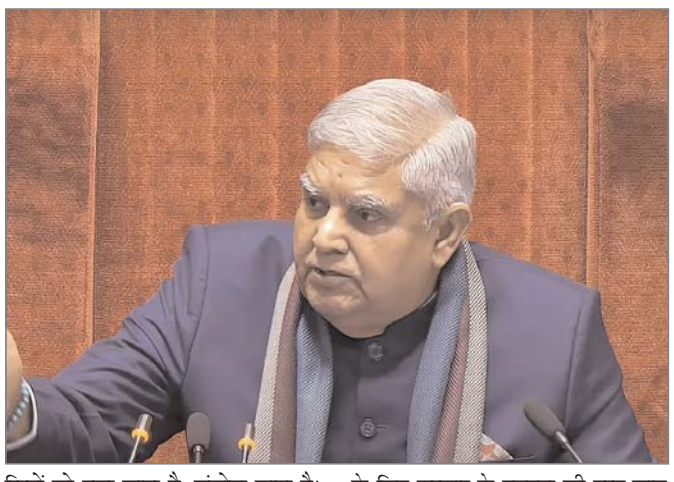

आप तो रिश्तों को बहुत जल्दी भूल जाते हो। आपको रिश्ते याद ही कहां रहते हैं। रिश्तों की अहमियत समझो थोड़ा। इन रिश्तों की तिलांजलि नहीं दी जाती है। इस

रिश्तों को पूजा जाता है, संजोया जाता है। उनका यह बयान विपक्ष के उस आरोप के संदर्भ में था, जिसमें कहा गया था कि सभापति धनखड़ अपनी अगली पदोन्नति के लिए सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं और उनके आचरण ने राज्यसभा की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनका व्यक्तिगत रूप से धनखड़ से कोई विरोध नहीं है, लेकिन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह कदम उठाना पड़ा।

विपक्षी दलों ने सभापति को हटाने के लिए नोटिस दिया है, जिसके बाद सत्तारूढ़ बीजेपी ने खुलकर उनका बचाव किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस धनखड़ पर आक्षेप लगा रही है, ताकि पार्टी के अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस के साथ रिश्तों पर उठाए जा रहे सवालों से ध्यान भटकाया जा सके। इस विवाद के बीच, हर्ष महाजन का बीजेपी से जुड़ना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। महाजन पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को मात दी थी। बता दें कि जगदीप धनखड़ भी कुछ समय कांग्रेस में थे।

सीरिया से लौटे पहले भारतीय ने बताए दमिश्क के भयावह हालात

नई दिल्ली (एजेंसी)। सीरिया में बशर अल-असद का तख्तापलट होने और उनके देश छोड़कर भागने के बाद वहां हालात भायवह बने हुए हैं। इस भयावह स्थिति में कुछ भारतीय भी फंसे थे जिन्हें वहां से बाहर निकाल लिया गया है। सीरिया से भारत लौटने वाले 75 भारतीयों में से पहले गाजियाबाद के रहने वाले रवि भूषण हैं। भारत लौटने पर रवि ने दमिश्क की भयावह स्थिति का जिक्र किया और मदद के लिए भारत सरकार को धन्यवाद कहा। रवि भूषण ने ,ह्रद्ब को बताया कि भारत ने अपने नागरिकों को वापस घर लाने में मदद के लिए किस तरह के प्रयास किए। रवि ने कहा कि भारत ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है और हम पहली टीम हैं जिन्हें सीरिया से बचाकर देश वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने (भारतीय दूतावास) हर एक व्यक्ति से संपर्क किया है, उनका उत्साहवर्धन किया साथ ही पूछा कि...क्या वो ठीक हैं।

विचार

आयुष्मान' पर केंद्र व दिल्ली सरकार में घमासान

आयुष्मान योजना को लेकर केन्द्र और दिल्ली की आप सरकार के बीच विवाद स्पष्ट रूप से दिखता है। हालांकि यह विवाद मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा है, परन्तु यह केवल इस योजना तक सीमित नहीं है। दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार के बीच पिछले एक दशक में कई अन्य जनहितकारी योजनाओं पर भी मतभेद सामने आए हैं। दोनों सरकारों के बीच यह टकराव राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बढ़ता ही जा रहा है, जिससे जनता को योजनाओं का लाभ उठाने में कई बार असमंजस का सामना करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि वह आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रही, जिससे दिल्ली के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा सांसदों द्वारा दायर जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की। कैसी विडम्बना है कि सरकार जन कल्याण के हित को नजरंदाज कर राजनीतिक विचारधाराओं के टकराव का रास्ता अख्तियार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद विधानसभा में घोषणा की थी कि वे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना को खुद लागू करेंगे। लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया। इसके पीछे आप की राजनीतिक जिद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर 6.5 लाख से अधिक पात्र परिवारों और 70 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को केंद्र की आयुष्मान योजना से वंचित कर रही है। इसके विपरीत, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि उनकी सरकार पहले से ही दिल्लीवासियों को मुफ्त इलाज दे रही है और स्वास्थ्य सुविधाएं उनकी प्राथमिकता हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आयुष्मान योजना लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे दिल्ली सरकार की मौजूदा योजनाओं को बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि दोनों योजनाओं में कुछ विरोधाभास हैं। आयुष्मान योजना में कुछ शर्तें और श्रेणियां हैं, जिनके तहत यदि किसी परिवार के पास फ्रिज, दोपहिया वाहन या पक्का मकान हो, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, आयुष्मान योजना में एक परिवार के लिए प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक इलाज की सीमा तय की गई है। यदि एक परिवार में दो लोग बीमार होते हैं, तो अतिरिक्त खर्च उन्हें अपनी जेब से करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि इलाज का खर्च 10 लाख रुपये है, तो पांच लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान परिवार को करना होगा। इसके विपरीत, दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना में कोई खर्च सीमा नहीं है।

मध्यप्रदेश का लक्ष्यः सशक्त स्वास्थ्य सेवाओं से स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण

राजेन्द्र शुक्ल (उप मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच है कि भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले उसके नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी उद्देश्य के तहत मध्यप्रदेश में भी राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य का उद्देश्य है कि न केवल नागरिकों को उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाए, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत और सक्रिय बनाया जाए। यह दृष्टिकोण केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों को बीमारी से पहले ही रोकथाम के उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

स्वास्थ्य सुविधाओं तक सुगम और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करनाः मध्यप्रदेश सरकार सभी नागरिकों तक सुलभ और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक के लिए न केवल सुलभ हों, बल्कि किफायती भी हों, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इसके तहत ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (ष्ट।ॾष्ट) को जिला अस्पतालों के समकक्ष सुविधाओं से लैस करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को छोटी बीमारियों के लिए जिला या बड़े अस्पतालों में जाने की आवश्यकता न हो। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने ही इलाके में इलाज मिल सकेगा, बल्कि जिला अस्पतालों पर भी दबाव कम होगा।

संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों के प्रबंधन में सुधार और बेहतर प्रबंधन के प्रयास किये जा रहे हैं। आपातकालीन और ट्रॉमा सेवाओं को भी सशक्त किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में 162 गहन चिकित्सा इकाइयाँ (ढ्ढष्टह्व) संचालित हो रही हैं, जिनमें 1,584 ढ्ढष्ट बेड और 1,003 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। यह सुविधाएं गंभीर रोगियों को बेहतर इलाज प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि ढ्ढष्ट और अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की संख्या में वृद्धि की जाए और आवश्यकतानुसार उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और उपकरणों का विस्तारः मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। इसके तहत सीटी स्कैन और डायलिसिस जैसी विशेष सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। ष्ट।ॾष्ट स्तर के ऊपर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी (ष्टक्र) प्रणाली की सुविधा दी जा रही है ताकि सटीक और समय पर निदान संभव हो सके। इसके अलावा, चुने गए जिला अस्पतालों में स्न्रढ्ढ, इकोकार्डियोग्राफी, और लैप्रोस्कोपिक सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है। राज्य के कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्ढ्ढह्रष्ट, ष्टञ्ज, स्न्रढ्ढ और क्कश्वञ्ज ष्टञ्ज स्कैन सेवाओं की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे गंभीर बीमारियों का उन्नत उपचार संभव हो सकेगा। इसके अलावा, कैंसर जैसे गंभीर रोगों के लिए 42 एंटी-कैंसर दवाओं की समयबद्ध डिलीवरी की व्यवस्था भी की गई है, जिससे मरीजों को सही समय पर दवा मिल सके।

चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धताः मध्यप्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी एक बड़ी चुनौती है। राज्य के कई सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण नागरिकों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में असुविधा होती है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत नए डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है और उन्हें आकर्षक वेतनमान, बेहतर कार्य सुविधाएं और अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि वे सरकारी सेवा में आकर अपना योगदान दें। साथ ही, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है ताकि अधिक से अधिक डॉक्टर तैयार हो सकें।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार चिकित्सकों को समय-समय पर प्रमोशन और वेतन वृद्धि के माध्यम से भी प्रोत्साहित कर रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में 1,607 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और सितंबर 2024 तक 1,902 बॉन्ड डॉक्टरों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं और इससे राज्य में चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सकेगा।

मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधारः मध्यप्रदेश में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। राज्य की मातृ मृत्यु दर (स्रूक्र) 173 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसे कम करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सतत विकास लक्ष्यों (स्ष्ठत्र) 2030 को प्राप्त करने के उद्देश्य से ढ्ढक्क॥स् 2022 मानकों के तहत स्वास्थ्य सेवाओं और मानव संसाधनों का उन्नयन किया जा रहा है। इसके साथ ही, सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकीकृत किया है ताकि बेहतर समन्वय और प्रबंधन हो सके।

महिलाओं की गर्भावस्था और शिशुओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 62 विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ (स्हृष्ट) स्थापित की हैं, जहां गंभीर रूप से बीमार नवजातों का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा, 199 नवजात स्थिरीकरण इकाइयाँ (हृक्चस्) भी स्थापित की गई हैं, जो मातृत्व वार्ड के निकट स्थित हैं ताकि बीमार और कम वजन वाले नवजातों का बेहतर देखभाल किया जा सके। शिशुओं के इलाज के लिए राज्य भर में 64 बाल गहन चिकित्सा इकाइयाँ (क्कढ्ढष्ट) भी स्थापित की गई हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का समय से चिन्हांकन कर बेहतर प्रबंधन की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सके।

आयुष्मान भारत योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय में लाया है क्रांतिकारी बदलावः आयुष्मान भारत योजना के तहत, मध्यप्रदेश में अब तक 22.22 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आयुष्मान कार्ड जारी करने में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। यह योजना गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। वर्तमान में, राज्य के 1,048 स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सूचीबद्ध हैं, जिनमें 493 सार्वजनिक अस्पताल और 555 निजी अस्पताल शामिल हैं। इस योजना के तहत 1,952 स्वास्थ्य लाभ पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें कैंसर, हृदय रोग, उच्च जोखिम गर्भावस्था, किडनी की बीमारियों और अन्य महंगे उपचार शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना में शामिल करने का प्रावधान किया है। यह वरिष्ठ नागरिकों के देश के विकास में योगदान का सम्मान है। वृद्धजन सहित सभी नागरिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सके और उनका सही उपचार हो सके। नियमित चिकित्सा जांच करवाना, स्वस्थ जीवनशैली अपनाना अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सकीय जांच सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्तमान में, जिला अस्पतालों और सिविल अस्पतालों में 132 प्रकार की जांच सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 80 प्रकार की जांचें की जा रही हैं। प्रदेश में 324 हब और 1610 स्पोक स्थापित किए गए हैं, जहाँ प्रतिदिन 35,000 से अधिक जांचें जिला स्तर पर और 32,000 से अधिक जांचें हब और स्पोक पर हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, सभी जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस, सीटी स्कैन और डिजिटल एक्स-रे की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे रोगियों को समय पर और निःशुल्क जांच की सुविधाएं मिल रही हैं।

इसके साथ ही, निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ है। जिला अस्पतालों में दवाओं की संख्या 295 से बढ़ाकर 530 की गई है, सिविल अस्पतालों में 448, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 373 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 299 प्रकार की दवाएँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

प्रधानमंत्री ग्लोबल मेडिसिटी योजना और चिकित्सा पर्यटन का विकासः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ग्लोबल मेडिसिटी योजना के तहत मध्यप्रदेश में मेडिकल हब का विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह हब राज्य के प्रमुख शहरों में स्थापित किए जाएंगे और चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से राज्य को एक वैश्विक स्वास्थ्य गंतव्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इन मेडिसिटी हब में अत्याधुनिक सुपरस्पेशलिटी और मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, आयुष चिकित्सा सेवाएं, हक्क्ष्ठ और डे केयर सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मेडिकल कॉलेजों का विस्तारः राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं और तीन नए मेडिकल कॉलेजों (सिवनी, नीमच और मंदसौर) को वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किए गये हैं। इसके अलावा, आठ अन्य मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं जो अगले तीन वर्षों में स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (क्कक्कक्क) मॉडल के तहत भी 12 अंडर-सर्व्ड जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना बनाई है। इसके तहत जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मॉडल के माध्यम से सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को दूरदराज के और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाना चाहती है, जिससे वहां की आबादी को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें।

इन सभी प्रयासों के माध्यम से, मध्यप्रदेश न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। सरकार का यह प्रयास है कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों और राज्य को एक मजबूत और स्वस्थ समाज की दिशा में अग्रसर किया जा जा सके।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के माध्यम से मध्यप्रदेश को देश में स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। सरकार के इन प्रयासों से न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। इसके साथ ही, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों को, ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके और उनकी जीवनशैली में सुधार हो।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, मध्यप्रदेश सरकार निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार और विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजनाएं न केवल राज्य की जनता के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, बल्कि यह अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। इन प्रयासों के साथ, सरकार का लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश न केवल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अग्रणी बने, बल्कि एक सशक्त और स्वस्थ समाज की स्थापना कर देश की प्रगति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे।

डीटीसी की खस्ता हालत, दिल्ली की महिलाओं के साथ हो रहा है बड़ा धोखा

आतिशी ने डीटीसी कर्मचारियों से मुलाकात करने की तस्वीरों को बुधवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया, आज डीटीसी कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान देखकर सुकून मिला। अपनी मांगें पूरी होने के बाद आज वे सचिवालय आए थे, हमने साथ बैठकर चाय पी। ये सिर्फ़ कर्मचारी ही नहीं, हमारे अपने परिवार के लोग हैं। यही लोग सड़कों पर हमारी दिल्ली को चलाते हैं, दिल्ली की लाइफ़लाइन हैं। हमें गर्व है कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने उनकी समस्याओं को सिर्फ़ 3 हफ्तों में हल कर दिया।

विडंबना देखिए कि, दिल्ली की जो आप सरकार डीटीसी कर्मचारियों की समस्याओं को सिर्फ 3 सप्ताह में हल करने का दावा कर रही है, वह वर्ष 2015 से लगातार सत्ता में है। यानी चुनाव का समय आ गया तो समस्याओं की भी याद आ गई।

हालांकि एक बात सही है कि डीटीसी, दिल्ली की लाइफ़लाइन हैं। दिल्ली मेट्रो के महंगे किराए को नहीं झेल पाने वाले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए डीटीसी आज भी परिवहन का एकमात्र साधन बना हुआ है। लेकिन दिल्ली की लाइफलाइन डीटीसी आज स्वयं अपने जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन ढूंढ रही है। डीटीसी की ज्यादातर बसों की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है और विशेष अनुमति लेकर इन्हें मजबूरी में चलाया जा रहा है। डीटीसी की हालत इतनी खराब हो गई है कि बीच सड़क पर बसों के खराब होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। छोटी-छोटी खराबियों के कारण भी बसें डिपो में पड़ी रहती है।

दिल्ली सरकार के इस रवैये को दिल्लीवासियों और खासकर महिलाओं के साथ एक बड़ा धोखा माना जा सकता है। क्योंकि आप सरकार ने फ्री बस यात्रा के नाम पर दिल्ली की महिलाओं को ऐसा झुनझुना थमाया हुआ है, जिसकी सच्चाई अब सामने आती जा रही है। दिल्ली की सड़कों से बसें गायब है। दिल्ली में जरूरत की तुलना में इतनी कम बसें सड़कों पर दौड़ रही है कि महिलाओं और लोगों को घंटों तक बस स्टॉप पर इंतजार करना पड़ता है। मजबूरी में महिलाओं और अन्य यात्रियों को अनाप-शनाप भाड़ा देकर बैटरी वाले रिक्शा या ग्रामीण सेवा में सफर करना पड़ता है। बाहरी दिल्ली और यमुना पार के इलाकों की हालत तो और भी बुरी है। अति व्यस्तम और ज्यादा सवारियों वाले बस रूटों पर भी बस की संख्या इतनी कम कर दी गई है कि हालत लगातार भयावह होते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक जमाने में जिस सुंदर नगरी में अनशन किया था, अगर वह बिना किसी ताम-झाम के उसी बस स्टॉप पर चले जाएं या उससे महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सीमा पुरी डिपो या नंद नगरी डिपो पर चले जाएं तो सारी सच्चाई उन्हें पता लग जाएगी।

बड़ी बात तो यह है कि, अगर किसी तरह से महिलाओं को बस मिल भी जाती है तो उनके साथ ड्राइवर और कंडक्टर का व्यवहार भी बहुत ही अपमानजक होता है। डीटीसी के कई ड्राइवरों और कंडक्टरों को लगता है कि महिला सवारी उनके पैसे से फ्री में सफर कर रही है। हालात कितने खराब हो गए हैं कि इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि डीटीसी बसों में रोजाना सफर करने वाली महिलाएं भी अब यह कहने लगी हैं कि फ्री बस सेवा उनके लिए सजा की सेवा बन गई हैं। उनसे भले ही किराया ले लो लेकिन बस की संख्या और सर्विस को तो ठीक कर दो। बस स्टॉप पर सही तरीके से बस कैसे रोका जाता है, यह भी ड्राइवर अब भूलते जा रहे हैं।

इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं के साथ किए जा रहे इस धोखे को वाकई बंद करना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही डीटीसी बसों का असली आंकड़ा जारी करना चाहिए। प्रत्येक रूट पर कितनी बसें दौड़ रही हैं और उसकी एक्चुअल टाइमिंग क्या है, यह भी जारी करना चाहिए। अगर कोई बस बीच रास्ते मे खराब हो जाती है तो रियल टाइम पर वह डेटा सोशल मीडिया पर अपलोड और अपडेट होना चाहिए। ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल को सवारियों खासकर महिलाओं के साथ बातचीत करने की स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए। इन सबकी जानकारी सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर आनी चाहिए। इसके साथ ही शिकायत निवारण की भी उचित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस बार दिल्ली के महिलाओं की नाराजगी उन पर भारी पड़ सकती है।

वश्व एड्स दिवस पर आयोजित हुई जन जागृति गतिविधियां

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। विश्व एड्स दिवस एक दिसंबर के अवसर पर रविवार को सीधी जिले के जेल में कैदियों के साथ विश्व एड्स दिवस का कार्यक्रम संपादित किया गया। जिला नोडल अधिकारी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम डॉ हिमेश पाठक ने बताया कि जन-जागरूकता कार्यक्रम जिला चिकित्सालय सीधी एवं ग्राम सुधार समिति सीधी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष जेल अधीक्षक रविशंकर पटेल एवं विशिष्ट अतीथि के रूप में उप अधीक्षक के के तिवारी जिला चिकित्सालय से संतोष तिवारी, के वी के सिंह, जरीना बेगम, भारती वर्मा, इंदल सिह संपूर्ण सुरक्षा केंद्र से परियोजना प्रबंधक वेदांती मिश्रा, अर्चना पाठक, लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना प्रबंधक मीरा गौतम पूनम सिंह, फूलकली तिवारी, सीमा सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न कराया गया।

सर्वप्रथम जेल के कैदियों को मानव श्रृंखला में बैठाया गया। एड्स जागरूकता के संबंध में नारे लगवा कर कार्यक्र म की शुरुआत की गई। कार्यक्र म को आयोजित करने का उद्देश्य बताया गया कि एड्स लाइलाज बीमारी है अभी इसकी कोई भी दवा अपने पूरे भारत वर्ष में नहीं बन पाई है। एड्स से सावधानी ही बचाव है। जरीना बेगम के द्वारा बताया गया कि हम एचआईवी जैसे संक्र मण को दूर करने का परामर्श देते हैं। काउंसलर इंदल सिंह के द्वारा कहा गया कि हम लोग इंजेक्टीबल ड्रग यूजर को इंजेक्शन का नशा छोड़ने के लिए दवाई देने का काम करते हैं। जोखिम पूर्ण व्यवहार करने वाले को एचआईवी संक्र मण से बचाने का काम करते हैं। उमा सेन के द्वारा बताया गया कि एचआईवी और एड्स की जानकारी अभी तक गांव के लोगों को नहीं है इसलिए इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार समुदाय के लोगों के साथ करने की आवश्यकता है। कार्यक्र म की अध्यक्षता कर रहे पुलिस जेल अधीक्षक रविशंकर पटेल जी द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि आज इतना बड़ा कार्यक्र म कैदियों के साथ में करने की जरूरत क्यों पड़ी यह हम सब लोग अपने दिमाग में सोच रहे होंगे लेकिन आप सबको मालूम हो एचआईवी और एड्स एक खतरनाक बीमारी है इस बीमारी से बचने के लिए हम सब लोगों को सुरक्षित जीवन जीने की आवश्यकता है इसके प्रति हमें वफादार रहने की जरूरत है इसके लिए जानकारी ही बचाव है। कार्यक्रम का संचालन संपूर्ण सुरक्षा केंद्र के परियोजना प्रबंधक वेदांती प्रसाद मिश्रा के द्वारा किया गया।

मऊगंज में खड़ा हो रहा भाजपा का आदर्श संगठन

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। भारतीय जनता पार्टी मऊगंज जिला संगठन चुनाव को लेकर जिला स्तरीय एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई कार्यशाला का शुभारंभ महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्राज्वलन के साथ पार्टी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला अध्यक्ष द्वारा किया गया जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी सदानंद गौतम ने कहा कि मऊगंज जिला संगठन पर्व के तहत निर्वाचनप्रक्रिया को पूर्ण करने का काम किया है स्थानीय समिति के गठन से लेकर उसे सर्व स्पर्शी स्वरूप देने का काम हुआ है मंडल चुनाव में क्षमताबान और विचारवान लोगों का चुनाव कर संगठन को सर्वव्यापी बनाने में आप सभी उपस्थित जन योगदान दें जिस तरह से आप सभी ने सदस्यता अभियान से लेकर सक्रिय सदस्यता और स्थानीय समितियां का चुनाव निर्विवाद पूर्ण किया है उसे से आपकी कार्यक्षमता की चर्चा हो रही है भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ राजेंद्र मिश्रा ने कार्यशाला कोसंबोधित करते हुए कहा कि मऊगंज जिला आदर्श संगठन के रूप में खड़ा हो रहा है पार्टी के विचारवान कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान से लेकर उसे स्थानीय स्तर पर खड़ा करने में बड़ी माहिती भूमिका का निर्वहन किया है मऊगंज के सभी कार्यकर्ता ने परिवार भाव से स्थानीय समिति क़ो खड़ा किया है और खासकर महिलाओं को पार्टी के निर्देशों के अनुरूप हर स्थानीय समिति में पदाधिकारी बनाकर सशक्त नेतृत्व खड़ा करने के लिए काम हुआ है मऊगंज जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने महत्व लगन से संगठन पर्व को सफल बनाया है सत्य प्रतिशत स्थानीय समितियां का गठन कर ऐतिहासिक काम हुआ है यह सब कार्यकर्ताओं की मेहनत अनुभवी नेतृत्व की वजह से संभव हुआ है मंडल का चुनाव भी समन्वय और सर्वसम्मतसे पूरा किया जाएगा मऊगंज को पूरे प्रदेश में आदर्श संगठनात्मक जिले के रूप में खड़ा करेंगे बैठक में सा जिला निर्वाचन अधिकारी शिवदत्त मिश्रा महेंद्र प्रताप सिंह सरिता सिंह बी सैलानी विपिन मिश्रा उर्मिला सिंह प्रकाश चौरसिया सहित पार्टी पदाधिकारी उपस्थित हुए।

सिंगरौली में पुलिस वाहन को बेकाबू पिकअप ने मारी टक्कर

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। सिंगरौली में शनिवार को पुलिस का वाहन हादसे का शिकार हो गया। हादसा सड़क दुर्घटना में दम तोड़ चुके युवक के शव को पीएम कराने बैढ़न लाते समय हुआ। राजासरई में पुलिस वाहन और पिकअप में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। जिसमें पुलिस वाहन का एक हिस्सा क्षतिगस्त हो गया। इस घटना में प्रधान आरक्षक सचिन सिंह सहित चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। बरगवां थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा के अनुसार बरगवां थाना क्षेत्र के चरकी पहाड़ी में शनिवार की दोपहर बाइक से जा रहे युवक धर्मेन्द्र साकेत की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने बरगवां पुलिस को सूचना दी। मौके पर थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा अपने दल-बल के साथ पहुंचे। मृतक युवक के शव को पुलिस वाहन से पीएम कराने के लिए बैढ़न भेजवाया जा रहा था। पुलिस के वाहन में प्रधान आरक्षक सचिन सिंह और चालक जागेश्वर पाल के साथ मृतक के दो परिजन जा रहे थे। जैसे ही पुलिस का वाहन राजासरई पहुंचा तो सामने से आ रहा पिकअप वाहन से टकरा गया। इस घटना में प्रधान आरक्षक सचिन सिंह और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

दिव्यांग छात्रावास के 14 बच्चे बीमार, फूड पॉयजनिंग की आशंका

बच्चों ने क्या खाया जिम्मेदारों को पता नहीं

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी जिले के दिव्यांग छात्रावास मधुरी में बड़े स्तर पर लापरवाही का मामला सामने आया है। खराब खानपान के कारण 14 बच्चों को फूड पॉयजनिंग हो गई, जिनमें से दो बच्चों की हालत गंभीर हो गई थी। सभी बच्चों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बता दें कि उल्टी-दस्त और डिहाइड्रेशन की समस्या से पीड़ित बच्चों की उम्र 8 से 15 वर्ष के बीच है। शनिवार को दिव्यांग बच्चों की ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता में ले जाया गया था। वहां लंच के पैकेट बच्चों को दिए गए थे। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि पैकेट वाला खाना खाने के बाद ही बच्चों की तबीयत खराब हुई। इस पूरे घटनाक्रम में बच्चों का बयान अधिकारियों के बयान से मैच नहीं कर रहा है। बच्चों का कहना है कि उन्होंने दाल चावल रोटी सब्जी सुबह खाई थी उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं खाया। लेकिन अधीक्षक का कहना है कि लंच पैकेट की व्यवस्था की थी उसे खाकर बच्चे बीमार हुए। पर जब डीपीसी अधिकारी से बात की गई तब उन्होंने बताया कि ठंड लगने की वजह से बीमार हुए हैं। हालांकि सभी के बयान में एकजुटता नहीं पाई जा रही है, जिसके लिए कलेक्टर ने जांच टीम का गठन कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम गोपद बनास नीलेश शर्मा ने जिला चिकित्सालय का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने घटना को गंभीरता से लेते हुए छात्रावास प्रबंधन की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई और जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने एसडीएम और सिविल सर्जन को बच्चों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

छात्रावास प्रबंधन पर सवाल: स्थानीय लोगों और बच्चों के अभिभावकों ने छात्रावास के प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। पहले भी खराब खानपान को लेकर शिकायतें मिल चुकी हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह घटना प्रबंधन की घोर लापरवाही को उजागर करती है।

बीआरसीसी ने की गई थी लंच पैकेट की व्यवस्था: दिव्यांग छात्रावास मधुरी के अधीक्षक रामसहाय साकेत द्वारा बताया गया कि विकासखंड स्तरीय दिव्यांगो के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जीडीसी कॉलेज मैदान में किया गया था। जहां लगभग दो बजे लंच पैकेट का वितरण किया गया, जिसे खाने के बाद बच्चे छात्रावास आ गए। दोपहर करीब तीन बजे से बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने लगा, अपने स्तर से छात्रावास में दवा करवाई गई। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तब जिला अस्पताल शाम के समय ले आया हूं, जहां उपचार चल रहा है। लंच पैकेट की व्यवस्था बीआरसीसी के द्वारा करवाई गई थी।

सिविल सर्जन बोले- चिंता की बात नहीं

पूरे मामले मे सीधी अस्पताल की सिविल सर्जन दीपा रानी इसरानी ने जानकारी देते हुए बताया है दिव्यांग छात्रावास मधुरी के 14 बच्चों को उल्टी-दस्त की समस्या के कारण जिला चिकित्सालय सीधी में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य की लगातार निगरानी रखी जा रही है। बच्चों की उम्र 8 से 15 वर्ष के बीच है, उन्हें बच्चा वार्ड में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार है। डिहाइड्रेशन के कारण दो बच्चों को ड्रिप लगाई गई है। किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है।

चंदई में जिला पंचायत सदस्य गीता मांझी ने किया भूमिपूजन

मीडिया ऑडीटर, त्यौंथर (निप्र)। रीवा जिले के त्यौंथर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदई में जिला पंचायत निधि से 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नाली का भूमि पूजन किया गया भूमि पूजन वार्ड क्रमांक 21 की जिला पंचायत सदस्य गीता मांझी ने किया इस दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव रोजगार सहायक के साथ अच्छी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे हैं। इस दौरान गीता मांझी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की समस्याओं के बारे में भी जाना है एवं त्वरित निदान करने का प्रयास किया है।

त्यौंथर विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र का किया भूमिपूजन

मीडिया ऑडीटर, त्यौंथर (निप्र)। कटरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बन जाने से ग्रामीणों को बीमारियों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उक्त बातें विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कटरा में 2 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 10 बिस्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन अवसर पर कही। इन्होंने कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम सबको मिलकर काम करना है।मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार जनता की हर मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने का कार्य कर रही है। शुद्ध पीने का पानी, सड़क, बीमार के लिए इलाज का प्रबंध, पढ़ाई की व्यवस्था, घर, बिजली, युवाओं को रोजगार जैसी अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास हो रहा है।

उन्होंने कहा कि त्यौंथर की जनता का मेरा पूरा परिवार ऋणी है।अपने इस परिवार के लिए मै जितने भी करू कम है।एक साल में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए विधायक ने कहा कि ध्वस्त पिछली व्यवस्था को सुधारने का कार्य हुआ ।एक साल में क्षेत्र 600 से अधिक ट्रांसफार्मर लगाए है। शिक्षा के क्षेत्र 2 सीएम राइज स्कूल त्यौंथर को मिली है ।18 से अधिक सड़के स्वीकृत हुई है।

507 लाख रुपए की लागत से लोनी बांध की नहरों के जीर्णोद्धार की राशि मंजूर हुई है, त्यौंथर में बाई नहर लिंक परियोजना की राशि मंजूर हुई है।400 एकड़ में औद्योगिक विकास केंद्र का निर्माण होगा ।5 एकड़ में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होगा। त्यौंथर के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। इस अवसर उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के दान दाता विश्वेश्वर प्रसाद मिश्रा का सम्मान किया एवं उनके परिजनों का विशेष आभार व्यक्त किया और कहा कि मानवता के लिए आपके द्वारा किए गए कार्य को आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेगी।कार्यक्रम का सफल संचालन विष्णु मिश्रा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने की। इस अवसर वरिष्ठ भाजपा नेता कौशलेश द्विवेदी, डॉ. ओम प्रकाश मिश्रा, अशोक पांडेय,विद्या सागर शुक्ला लाला,ममता संवेद्र शर्मा,राजेश सोनी,मनीष सिंह,संदीप त्रिपाठी राजेंद्र वर्मा,वशिष्ठ सोनी शुक्कल देवी,शिवरतन नामदेव ,इंद्रलाल मिश्रा,नागेंद्र द्विवेदी अवनीश कारपेंटर ,मनीष मिश्रा,राहुल गुप्ता,प्रेमलाल वर्मा ,राम जतन यादव अशोक गुप्ता वेद प्रकाश तिवारी कृपाशंकर पांडेय,वेद मिश्रा,रावेंद्र तिवारी काली चरण मिश्र,आरपी तिवारी ,अनुपम तिवारी ,अंकित शुक्ला समेत हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

वार्षिक एथलेटिक्स आयोजित, जिले के 7 कॉलेजों के स्टूडेंट्स हुए शामिल

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, संजय गांधी महाविद्यालय सीधी में कॉलेज में वार्षिक एथलेटिक्स खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार के दिन किया गया। जहां सीधी जिले के सभी ब्लॉक में संचालित महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। यह कार्यक्रम सीधी के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित किया गया।

सीधी जिले में संजय गांधी कॉलेज के अलावा अवधेश प्रताप सिंह विवि की करीब 6 शाखाएं अन्य इसमें शामिल हुईं। उन्होंने सभी एथलीट कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेक, दौड़ और क्रिकेट सहित अन्य खेलों का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीधी विधायक रीति पाठक उद्घाटन में मौजूद रहीं। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों में जीत और हर का महत्व नहीं होना चाहिए, केवल अपने महाविद्यालय और अपने जिले का नाम रोशन करें। इसके लिए चिंता करनी चाहिए। कभी भी अपने आपको श्रेष्ठ ना माने ताकि हमारा जिला और भी बेहतर हो सके।

सर्वेयर को खनिज निरीक्षक का प्रभार देने पर विवाद, हाईकोर्ट की फटकार पर नेता प्रतिपक्ष का तंज

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने नियम विरुद्ध 13 नवंबर को आदेश जारी कर एक सर्वेयर को खनिज निरीक्षक का प्रभार दे दिया। इसके खिलाफ असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर डॉक्टर वीके तिवारी 20 नवंबर को उच्च न्यायालय की शरण में गए।

मामले को गंभीरता से सुनते हुए न्यायाधीश ने असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर डॉक्टर वीके तिवारी को स्थगन दिया। वहीं जिम्मेदारों को नोटिस देकर जवाब मांगा हैं। अब इस मामले को लेकर रविवार को नेता-प्रतिपक्ष उमंग सिंघारने भ्रष्टाचार को सरकारी संरक्षण का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार को घेरने हुए ट्वीट किया है।

पिछले दिनों जिले के प्रभारी मंत्री संपत्तियां उइके के अनुमोदन से सर्वेयर मुनेंद्र सिंह को खनिज निरीक्षक बनाते हुए सरई और माड़ा का प्रभार दे दिया गया। जबकि हटाए गए सहायक खनिज निरीक्षक डॉक्टर वीके तिवारी को चितरंगी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया।

कलेक्टर के इस आदेश से सहायक खनिज अधिकारी डॉक्टर वीके तिवारी असहमत थे। उन्होंने कहा कि मेरा प्रभार बदलना सही था। लेकिन एक सर्वेयर को खनिज निरीक्षक बनाना नियम विरुद्ध है। वरिष्ठ अधिकारियों से नियम विरुद्ध प्रभार को लेकर चर्चा की गई लेकिन न्याय संगत जवाब नहीं मिला।

जिसके कारण मुझे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जहां उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश देते हुए जिम्मेदारों से जवाब मांगा है। वहीं चर्चा है कि आखिर सरकार की नीतियों और योग्यता पर नियम विरुद्ध तरीके से कौन सर्वेयर को निरीक्षक बना रहा है। हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ट्वीट करते हैं लिखा कि हाई कोर्ट का आदेश भ्रष्टाचार को सरकारी संरक्षण मिलने का प्रमाण ये रहा,जब मुख्यमंत्री कमजोर हो, तो अफसर पूरी व्यवस्था पर हावी हो जाते हैं। ये मामला ऐसा ही है, जिसमें सिंगरौली जिले में एक सर्वेयर को खनिज अधिकारी का प्रभार दिया गया। यह सब खनिज माफिया की सांठगांठ और उन्हें रायल्टी की चोरी में छूट देने के लिए दिया गया। लेकिन, हाईकोर्ट में यह चालबाजी नहीं चली, अदालत ने इस अपात्र को अधिकारी बनाने पर स्टे दे दिया।

11 दिसम्बर - 26 दि
जनक
पर्व

मुख्यमंत्री
डॉ. मोहन यादव द्वारा
₹758 करोड़ के विकास कार्यों का
भूमिपूजन एवं लोकार्पण
पूर्वाह्न 11 बजे | कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, भोपाल

रातापानी टाइगर रिजर्व का
लोकार्पण
प्रातः 10 बजे | गोल जोड़, भोपाल
13 दिसम्बर, 2024

मोहन यादव सरकार
काम लगातार-फैसले असरदार

समृद्ध हो रही संस्कृति

- मकर संक्रांति से गीता जयंती तक पूरे वर्ष के त्योहारों को प्रदेश सरकार ने समाज के साथ मिलकर मनाया।
- विक्रम सांस्कृतिक पर्व का 1 मार्च से 9 अप्रैल, 2024 तक आयोजन। कालजयी महानायकों पर केन्द्रित भारत के पहले संग्रहालय "वीर भारत न्यास" का शिलान्यास।
- विक्रमोत्सव पर विश्व की पहली "विक्रमादित्य वैदिक घड़ी" का शुभारंभ कर प्रदेश ने भारतीय काल गणना परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया।
- रक्षाबंधन पर बहनों के सम्मान में पूरे श्रावण माह प्रदेशव्यापी कार्यक्रमों ने बढ़ाई भाई-बहन के स्नेह की प्रतिष्ठा।
- गुरुजनों के सम्मान में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। अब हर वर्ष होगा गुरु पूर्णिमा पर्व का आयोजन।
- 1450 किमी लंबे श्रीराम वन गमन पथ निर्माण का निर्णय।
- श्रीकृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों (सांदीपनि आश्रम, नारायणा गांव उज्जैन, जानापाव इंदौर एवं अमझेरा धार) को जोड़ कर श्रीकृष्ण पाथेय का होगा निर्माण। श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के गठन को स्वीकृति।
- भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करते हुए पाठ्यक्रमों में रामायण और गीता वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल।
- अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर मध्यप्रदेश में बना गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड।
- प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन निर्माण का निर्णय।
- प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे।
- मां क्षिप्रा शुद्धिकरण एवं प्रवाहमान बनाए रखने का संकल्प पूरा करने के लिए ₹ 599 करोड़ की लागत की कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना का भूमिपूजन।

सुशासन की सरकार

- नामांतरण, बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण के लिये साइबर तहसील लागू। यह पहल करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य, साइबर तहसील 2.0 प्रारंभ।
- ई-पंजीयन एवं ई-स्टेम्पिंग के माध्यम से संपत्ति रजिस्ट्री हेतु संपदा 2.0 शुरू।
- राजस्व महाअभियान के दो चरणों में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा तरमीम और सीमांकन के 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा, राजस्व महाअभियान 3.0 प्रारंभ।
- थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य सम्पन्न।
- हर जिले में होगा पुलिस बैंड।
- जिला, संभाग, तहसील आदि की सीमाओं के पुनर्निर्धारण एवं युक्तिकरण के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित।
- 1972 के नियम को बदलते हुए सभी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपने वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान स्वयं करने का निर्णय।
- सुलभ आवागमन के लिए परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर बने चैक पॉइंट।
- खुले में मांस, मछली की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध।
- भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्णय।
- लाउड स्पीकर की अनियंत्रित एवं अनियमित आवाज का प्रयोग किया प्रतिबंधित।
- वारंट और समन की तामील के लिए ई-तकनीक का उपयोग प्रारंभ। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य।

नई जागृति के साथ पर्यावरण संरक्षण

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर आरंभ हुए 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को सफल बनाने के लिए मध्यप्रदेश ने साढ़े 5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प पूरा किया।
- जल स्रोतों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अभूतपूर्व पहल पर जलगंगा संवर्धन अभियान का आयोजन। पर्यावरण दिवस (5 जून) से गंगा दशहरा (16 जून) तक चला अभियान। ₹ 1384 करोड़ की लागत से 56 हजार से अधिक जल स्रोतों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार।
- 18 लाख से अधिक नागरिकों ने की जनभागीदारी।

अभूतपूर्व गति से औद्योगिक विकास

- वर्ष 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में किया गया घोषित।
- अब तक सम्पन्न हुई 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम से रु. 2.07 लाख करोड़ एवं मुंबई, बैंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता में किये गये रोड-शो कार्यक्रमों में ₹ 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश, भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में ₹ 20 हजार करोड़ के निवेश और यू.के. और जर्मनी की यात्रा में ₹ 78 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन संयुक्त प्रयासों से कुल ₹ 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
- प्रदेश के हर जिले में निवेश प्रोत्साहन केन्द्र प्रारंभ किये गए।
- मुरैना में मेगा लेदर, फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट पार्क की स्थापना का निर्णय।
- नर्मदापुरम जिले के मुहासा-बाबई इंडस्ट्री एरिया में रिन्युवल एनर्जी और एनर्जी से संबंधित उपकरणों की इकाइयों का भूमिपूजन।

आगे बढ़ते युवा

- युवाओं की शिक्षा एवं आधुनिक तकनीकों में योग्यता और कौशल निर्माण के साथ सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवा शक्ति मिशन प्रारंभ।
- सभी शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर की जा रही भर्तियां। आगामी 5 वर्ष में 2.50 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती का लक्ष्य। पदों की भर्ती के लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर होगा जारी।
- भारत सरकार के पीएलएफएस सर्वे में मध्यप्रदेश ने दर्ज की सबसे कम बेरोजगारी दर।
- मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत वर्ष 2024 में 20 हजार चयनित युवाओं को लगभग ₹ 41 करोड़ स्टाइपेंड वितरित।
- स्टार्ट-अप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए ₹ 50 हजार से लेकर ₹ 1.50 लाख तक वित्तीय सहायता।
- अग्निवीर योजना में युवाओं का चयन हो, इसके लिए 360 घंटे प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य। मध्यप्रदेश में पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को मिलेगा आरक्षण।
- प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का निर्णय।
- वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंतर्गत सभी जिलों में बनेंगे खेल स्टेडियम।।
- भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और रीवा के 6 विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना।
- वर्तमान में कुल 268 शासकीय आई.टी.आई. संचालित। इस वर्ष 22 नये आई.टी.आई. प्रारंभ करने से 5280 अतिरिक्त सीट्स की होगी वृद्धि।

जनजातीय समाज को समान अधिकार

- छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय एवं जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से जाने जायेंगे।
- विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण हेतु जनजातीय बटालियन गठित करने का निर्णय।
- तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय ₹ 3000 प्रति बोरा से बढ़ाकर किया ₹ 4000।
- पीएम जन-मन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में ₹ 7300 करोड़ से अधिक की लागत से हो रहे अधोसंरचना कार्य। 11 लाख से अधिक भाई-बहन लाभान्वित।
- पीएम जन-मन योजना अन्तर्गत देश में सर्वप्रथम जन-मन कॉलोनी शिवपुरी में बनाकर मध्यप्रदेश योजना में अग्रणी। देश की सबसे पहली जन-मन सड़क बालाघाट जिले में बनकर तैयार।
- युवाओं को यूपीएससी, पीएससी, सिविल जज, गेट, कैट आदि के लिए नि:शुल्क कोचिंग का निर्णय।

गरीब वर्ग को समान अवसर

- इंदौर के हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों को ₹ 224 करोड़ की लंबित राशि का भुगतान।
- संबल 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ 73 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन। 40 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को ₹ 895 करोड़ से अधिक का अंतरण।
- स्वामित्व योजना में 24 लाख भू-अधिकार पत्र वितरित कर प्रदेश देश में प्रथम।
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को ₹ 10 हजार से 50 हजार तक ऋण सहायता।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 55 लाख हितग्राहियों को ₹ 3 हजार करोड़ से अधिक राशि का अंतरण।
- 5 करोड़ पात्र हितग्राहियों को 30.59 लाख मी.टन खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत वितरित
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 36 लाख से अधिक परिवारों को एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 8 लाख से अधिक परिवारों को पक्का घर।

खुशहाली की ओर अन्नदाता

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की होगी स्थापना।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 81 लाख से अधिक किसानों को ₹ 4 हजार करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत ₹ 4 हजार 900 करोड़ का प्रावधान।
- रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम ₹ 3900 प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता।
- वर्ष 2024-25 बजट में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान। लगभग 32 लाख कृषक हो रहे हैं लाभान्वित।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-23' में 25 लाख से अधिक किसानों को ₹ 750 करोड़ से अधिक की राशि के दावों का हुआ भुगतान।
- किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस का भुगतान।
- सोयाबीन का ₹ 4,892 प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का निर्णय।
- 5 वर्षों में दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन दाल शुरू किए जाने का निर्णय। अरहर, मूंग, उड़द एवं मसूर जैसी सभी दालों के एमएसपी पर उपार्जन की व्यवस्था बनेगी मजबूत।

आत्मविश्वास से नारी शक्ति

- नारी सशक्तिकरण के प्रति सम्मान स्वरूप वीरा जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृ का जबलपुर में आयोजन।
- मां अहिल्या बाई के 300वें जन्म जयंती वर्ष एवं प्रदेश में हुए दशहरा शस्त्र पूजन कार्यक्रम।
- दमोह में रानी दमयंती संग्रहालय बनाने का निर्णय
- शासकीय सेवाओं में महिलाओं को मिलेगा अब
- लाड़ली बहना योजना में 1.29 करोड़ बहनों ₹ 19 हजार करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण
- प्रदेश की लगभग 26 लाख लाड़ली बहनों को ₹ के लिए वर्ष 2024 में ₹ 715 करोड़ से अधिक की
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 89 लाख महिला
- लाड़ली लक्ष्मी योजना में दिसम्बर 2023 से अब को ₹ 170 करोड़ की छात्रवृत्ति अंतरित।
- स्व-सहायता समूह के अंतर्गत लखपति दीदी यो और आत्मनिर्भर। 1 लाख से अधिक दीदियां बनीं
- 5 लाख स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 62 ला
- महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 850 एमए का अंतरण।
- सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना में 19 लाख से अ 18 लाख की राशि अंतरित।
- जेंडर बजट में ₹ 19 हजार 21 करोड़ से अधिक के लिए शासन के विभागों को ₹ 1 लाख 21 हजार क

सुलभ आधु स्वास्थ्य सु

- उज्जैन को मिली मध्यप्रदेश की पहली मेडि महाविद्यालय की सौगात। मेडिसिटी में सुपर अस्पताल, चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र जैसी अ
- पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए ग बीमार/दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एयरलिफ्ट कर सरकार की संवेदनशील पहल।
- आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से कर मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे। 70 वर्ष से अ भारत योजना में शामिल, ₹ 1381 करोड़ का प्राव
- वर्तमान में प्रदेश में 17 शासकीय एवं 13 निजी चि 8 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण चिकित्सा महाविद्यालय शीघ्र प्रारंभ होंगे।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य विलय सुशासन और कार्यदक्षता का उदाहरण क
- स्वास्थ्य संस्थानों में 46 हजार 491 नये पदों सृजन की स्वीकृति।
- जिला अस्पताल एवं सिविल अस्पतालों को ए का निर्णय।

D11119/24

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

सम्बर 2024

ल्याण

जनसेवा और मध्यप्रदेश के विकास के लिए निष्ठा और समर्पण का एक साल

त्वरित निर्णय बने मिसाल

"मैं प्रदेश के आठ करोड़ नागरिकों का आभारी हूं, जिनके सहयोग से हमारा प्रदेश आज अपने सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "विकसित भारत" के संकल्प के तहत, प्रदेश 'GYAN' गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के चार मुख्य स्तंभों पर आधारित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध प्रयासों से निरंतर आगे बढ़ रहा है।"

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

"गरीब, युवा, महिला और किसान, 'विकसित भारत' के लिए हम इन चारों स्तंभों को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने में जुटे हैं। देश में सिर्फ चार जातियां गरीब, युवा, महिलाएं और किसान हैं। मैं इन चारों जातियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूं। मेरा मानना है कि मूल आस्था और धर्म को छोड़कर इन चार मूल जातियों के उत्थान से ही देश प्रगति करेगा।"

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

...भरपूर ...त्ति

...ना रानी दुर्गावती के 500वें जन्म ...में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक

... विजयादशमी के अवसर पर पूरे

...5 प्रतिशत आरक्षण।

...को जनवरी 2024 से अब तक

...450 में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग ...राशि का अंतरण।

...ों को मिली धुएं से मुक्ति।

...तक 5 लाख 12 हजार बालिकाओं

...जना से महिलाएं बन रहीं सशक्त ...लखपति।

...ड बहनें हुईं आत्मनिर्भर।

...सएमई इकाइयों को ₹ 275 करोड़

...धिक बालिकाओं को ₹ 57 करोड़

...ी वृद्धि। महिला सशक्तिकरण के ...रोड़ का प्रावधान।

...निक ...विधाएं

...सिटी एवं शासकीय चिकित्सा ...स्पेशिलिटी एवं मल्टीस्पेशिलिटी ...केक सुविधाएं होंगी उपलब्ध।

...दस्थ क्षेत्रों से गंभीर रूप से ...इलाज उपलब्ध कराने के लिए

... अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित ...धिक आयु के बुजुर्ग भी आयुष्मान ...ान।

...चिकित्सा महाविद्यालय संचालित। ...धीन एवं पीपीपी मोड पर 12

...एवं परिवार कल्याण विभाग का ...ा।

...नियमित/ संविदा/आउटसोर्स) के

...-एक शव वाहन उपलब्ध कराने

सशक्त भविष्य के लिए शिक्षा

- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ।
- 369 सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज विद्यालयों का संचालन, वर्ष 2025 में लगभग 150 नये सीएम राइज विद्यालय होंगे संचालित।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश। नई नीति के तहत वर्ष 2025 से लगभग 3,200 प्राथमिक शालाओं में छोटे बच्चों के लिए प्री-प्राइमरी प्रारंभ होगी।
- ₹ 170 करोड़ से खरगोन में क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का उद्घाटन।
- सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ।
- शिक्षा को वैश्विक संस्थानों से जोड़ने के लिए 12 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एम.ओ.यू.।
- महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बस की सुविधा।

कायाकल्प की ओर शहरी विकास

- यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में बसों के लिये परिवहन कंपनी बनाकर संचालन किया जाएगा।
- प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (महानगर) का गठन किया जायेगा। इंदौर-उज्जैन-देवास-धार को मिलाकर एक तथा भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा-राजगढ़ को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाया जाएगा।
- भारत सरकार के विजन के अनुरूप राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों जैसे ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर, नर्मदापुरम, शहडोल आदि को भी क्षेत्रीय आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने की अवधारणा के साथ कार्य योजना बनाई जाएगी।
- संतुलित नगरीय विकास को गति देने तथा आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पुनर्घनत्वीकरण तथा पुनर्विकास नीति के अतिरिक्त एकीकृत टाउनशिप नीति तैयार की जाएगी। जिसमें निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में लाभ से वंचित सभी शहरी गरीब तथा मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों को आवास प्रदान किए जाएंगे।
- खाली मिलों जैसे हुकुमचंद/विनोद मिल एवं अन्य शहरों में खाली पड़ी शासकीय भूमियों पर शहरी प्रोजेक्ट लॉन्च किए जायेंगे।
- निर्माणाधीन महाकाल महालोक उज्जैन, संत रविदास लोक सागर, माँ नर्मदा महालोक अमरकंटक, देवी अहिल्या लोक खरगोन, नागलवाड़ी लोक बड़वानी, देवी लोक सलकनपुर, श्री रामराजा लोक ओरछा, जाम सांवली श्री हनुमान लोक-पांढुर्णा, श्री पशुपतिनाथ लोक मंदसौर, श्री परशुराम लोक जानापाव, महाराणा प्रताप लोक भोपाल, भादवामाता लोक नीमच, माँ पीताम्बरा लोक दतिया और माता मंदिर लोक रतनगढ़ को पूरा किया जायेगा।

नयी पहचान गढ़ता पर्यटन

- "पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा" का शुभारंभ। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सिंगरौली, उज्जैन एवं खजुराहो के मध्य शुरू हुआ संचालन।
- मध्यप्रदेश टाइगर और चीता स्टेट के बाद बना लेपर्ड स्टेट। भारत सरकार की रिपोर्ट अनुसार प्रदेश में 3907 तेंदुए हैं, जो कि देश में सबसे अधिक हैं।
- मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान को मिलाकर बनेगा चीता कॉरिडोर।
- प्राणपुर, सावरवानी एवं लाड़पुर खास को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार।

सेवा और संवर्धन गौ-संरक्षण

- वर्ष 2024 गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
- दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से हर ब्लॉक में एक गांव 'वृंदावन ग्राम' बनेगा।
- 10 से ज्यादा गाय पालने पर शासकीय अनुदान देने का निर्णय।
- दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच हुआ एमओयू। आगामी 5 वर्ष में लगभग 12000 दुग्ध समितियां 25 लाख लीटर दूध एकत्रित करने लगेंगी।
- ग्वालियर स्थित आदर्श गौ-शाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना।
- प्रत्येक 50 किमी पर घायल गायों के इलाज के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन का प्रबंध। 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयां प्रारंभ।

विकास को बल देती अर्थव्यवस्था

- वर्ष 2024-25 में 16% की बढ़ोतरी के साथ ₹ 3 लाख 65 हजार करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत
- अगले 5 साल में बजट को दोगुना करते हुए ₹ 7 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य
- आगामी वित्त वर्ष में शून्य बजट का प्रावधान करने का निर्णय।

प्रगति का आधार अधोसंरचना विकास

सड़क

- इंदौर में ₹ 350 करोड़ के एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर। भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना में भी बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर।
- ₹ 10 हजार करोड़ से अधिक की 724 किमी लम्बी विभिन्न 24 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास।
- भारत सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए ₹ 3 हजार 500 करोड़ की राशि स्वीकृत।
- उज्जैन-जावरा 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे निर्माण के लिए ₹ 5 हजार करोड़ से अधिक की स्वीकृति। इसके निर्माण से उज्जैन, इंदौर एवं आस-पास के क्षेत्र मुम्बई-दिल्ली 8 लेन इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर से जुड़ेंगे।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 8,565 गांव 19,378 किलोमीटर लंबी सड़कों से बारहमासी मार्ग से जुड़े।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 हजार कि.मी. की सड़कों के निर्माण एवं लगभग 2 हजार कि.मी. सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य।
- ₹3589 करोड़ की लागत से भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4-लेन में अपग्रेड करने की स्वीकृति।
- 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर की परियोजना स्वीकृत।

वायुसेवा

- ग्वालियर से बैंगलुरु, अहमदाबाद, ग्वालियर, दिल्ली और अयोध्या के लिए विमान सेवा प्रारंभ।
- विंध्य क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात। रीवा में मध्यप्रदेश का छठवें एयरपोर्ट का शुभारंभ।
- ग्वालियर में देश में सबसे कम समय में बनकर तैयार हुए, मध्यप्रदेश के सबसे बड़े राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट का उद्घाटन।

रेल

- ₹ 14440 करोड़ की लागत से भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल निर्माणाधीन।
- इंदौर-उज्जैन के मध्य शुरू होगी वन्दे मेट्रो ट्रेन।
- ₹ 18 हजार 36 करोड़ की इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना को स्वीकृति, 309 किमी लंबी रेल लाइन पर 30 नए रेलवे स्टेशनों से जनजातीय बहुल आकांक्षी जिला बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित निकटवर्ती जिले लाभान्वित होंगे।
- प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजनांतर्गत 33 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास एवं 133 रेल ओवर ब्रिज एवं अंडरपास का शिलान्यास एवं लोकार्पण।
- मध्यप्रदेश को 364 विभिन्न रेल परियोजनाओं की सौगात। प्रदेश को चौथी सेमी-हाईस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस (खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन) ट्रेन मिली।
- भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रख-रखाव और सुविधाओं के विकास हेतु लगभग ₹ 100 करोड़ की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास।

नवीकरणीय ऊर्जा

- 12 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन 14 गुना बढ़कर हुआ 7,000 मेगावॉट।
- 308 करोड़ रुपये की लागत से खरगोन जिले में जलूद ऊर्जा संयंत्र का भूमिपूजन।
- ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट से 278 MW विद्युत उत्पादन प्रारंभ।
- इंदौर को सोलर सिटी बनाने के लिए हर घर सोलर अभियान का संचालन।
- मुरैना में देश का पहला सोलर पॉवर स्टोरेज प्लांट लगाया जाएगा
- शाजापुर, आगर और नीमच में सोलर पार्क का निर्माण।

केन-बेतवा लिंक परियोजना

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 दिसम्बर को छतरपुर में परियोजना का शिलान्यास किया जायेगा।
- परियोजना से प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिलों में कुल 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेगी सिंचाई सुविधा
- प्रदेश की कुल 41 लाख आबादी होगी लाभान्वित

पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 दिसम्बर को परियोजना का शिलान्यास किया जायेगा।
- प्रदेश के मालवा क्षेत्र के 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर-मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर एवं मुरैना में 6.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेगी सिंचाई सुविधा।

अन्य सिंचाई परियोजनाएं

- ₹ 1320 करोड़ की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति। सिंगरौली जिले में परियोजना से लगभग 32 हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा।
- ₹ 4 हजार 197 करोड़ 58 लाख की लागत से जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति।
- प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित, वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य।

श्रीकृष्ण के जीवन की प्रत्येक घटना मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि के लोग मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पटलिया समाज के लोग गुजरात स्थित नवतनपुरी धाम जामनगर, महामंगलपुरी धाम सूरत और मध्यप्रदेश स्थित मुक्ति पीठ पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में जाकर दर्शन लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने यह घोषणा आज अलीराजपुर जिले के ग्राम रिंगोल स्थित लाडीबरिया फलिया में आयोजित श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव-2024 में की। उन्होंने अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद एवं स्वतंत्रता सेनानी परथिया बाबा की धरती को नमन किया। मुख्यमंत्री ने बरझर क्षेत्र में पुलिस थाने की स्थापना बोरकुंडिया में बिजली ग्रिड की स्थापना तथा चंद्रशेखर आजाद नगर विकासखंड क्षेत्र की लगभग 28 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव के अलौकिक दिव्य वातावरण में आकर मन आनंदित हो गया है। बुंदेलखण्ड के महाराज छत्रसाल को श्री प्राणनाथजी ने भेंट के रूप में तलवार दी। श्री प्राणनाथजी ने श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म संप्रदाय की स्थापना की तब से यथावत चल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि

श्रीकृष्ण के जीवन की प्रत्येक घटना मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक है। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई के मार्ग पर निरंतर चलने और कष्टों से गुजरने के बाद ही वे श्रीकृष्ण कहलाये। श्रीकृष्ण को मोर मुकुट धारण करने में आनंद मिलता है यही मोर मुकुट समूचे समाज की पहचान के रूप में सुशोभित होता है। राज्य शासन द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में कृष्ण लीलाओं को पढ़ाए जाने का समावेशन किया गया है। प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन की स्थापना की जाएगी। गीता कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अद्भुत संगम है जो अनेक रूपों में मानव जीवन को प्रभावित करती हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव में सर्वप्रथम गुरुजी श्री नटवरलालदास जी भट्ट (हरकुंडी गुजरात) की स्मृति में स्थापित ॐमूल मिलावाॐ के दर्शन कर परिक्रमा की। मूल मिलावा परमधाम में आत्मा का परमात्मा के मिलन को दर्शाता है। यहां पर भागवत जी एवं प्रणामी ग्रन्थों जैसे स्वरूप साहेब, वित्तक साहेब, ब्रह्मवाणी आदि 216 रखें ग्रंथों का अनुयायियों द्वारा महोत्सव के दौरान पाठ किया जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच पर स्थित गुरु गादी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव आयोजनकर्ताओं द्वारा वृहद पुष्पमाला एवं पारंपरिक साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही अलीराजपुर जिले संस्कृति को परिलक्षित करते चांदी के कड़े भेंट किए। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव-2024 गुरुजी श्री नटवरलालदास जी भट्ट के 46वें स्मृति महोत्सव के रूप में महाराज श्री रश्मिकांत एन. भट्ट जी के मार्गदर्शन में पांच दिवसीय 9 से 13 दिसम्बर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें श्रीमदभागवद श्रीकृष्ण कथा, ब्रम्हज्ञान, महायज्ञ का आयोजन किया जाता है।

श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म के श्री रश्मि कांत भट्ट महाराज, श्री स्वामी राज दास जी महाराज, श्री महेंद्र प्रसाद जी महाराज, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, जोबट विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल, पूर्व सांसद श्री गुमान सिंह डामोर, पूर्व विधायक श्री माधौसिंह डावर, जनपद अध्यक्ष श्री इंदर सिंह डावर, श्री विशाल रावत, रिंगोल के सरपंच श्री महेश भूरिया सहित बड़ी संख्या में पटलिया समाज के लोग उपस्थित थे।

एसीपी पर कानपुर आईआईटी स्टूडेंट से रेप का आरोप

कानपुर (एजेंसी)। कानपुर आईआईटी की एक स्टूडेंट ने एसीपी पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि कलेक्टरगंज एसीपी मोहसिन खान आईआईटी से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। वहां रिसर्च स्कॉलर से नजदीकी बढ़ गई। आईआईटी ने प्यार में फंसाकर उससे रेप किया। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के आदेश पर गुरुवार को साउथ अंकिता शर्मा और डीसीपी अर्चना सिंह सिविल ड्रेस में आईआईटी पहुंचीं। दोनों महिला अफसरों ने पूछताछ की। आरोप सही पाया गया। पुलिस कमिश्नर ने एसीपी के खिलाफ रेप समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। एसीपी को पद से हटा दिया है। डीसीपी शर्मा ने बताया कि आरोपी एसीपी को तत्काल प्रभाव से लखनऊ हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया गया है। (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) बनाई गई है। उसे ट्रैफिक अर्चना लीड कर रही हैं। टीम में एसीपी अभिषेक पांडे समेत 5 मेंबर होंगे।

सुप्रीम कोर्ट बोला-प्रताड़ना को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कह सकते

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति पर किसी की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोष तभी लगाया जा सकता है, जब इसका पुख्ता सबूत हो। सिर्फ प्रताड़ना का आरोप इसके लिए काफी नहीं है। यह टिप्पणी विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ ने 10 दिसंबर को गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले पर सुनवाई के दौरान दी। दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने एक महिला के उत्पीड़न और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में उसके पति और ससुराल वालों को बरी करने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए उन्हें महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब बेंगलुरु में 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला चर्चा में है। अतुल ने 24 पेज के सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और उसके घरवालों पर उसे प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। इसके आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है।

सीहोर में 7वीं कक्षा की बच्ची से गैंगरेप, वीडियो वायरल करने की धमकी

सीहोर (एजेंसी)। नगर के कस्बा क्षेत्र में 2 नवंबर को तीन युवकों ने नाबालिग से गैंग रेप किया और गलत काम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद वे पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगे। कोतवाली थाना प्रभारी मनोज मालवीय ने बताया, गुरुवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, नगर के कस्बा क्षेत्र की रहने वाली 11 वर्षीय नाबालिग कक्षा 7 में पढ़ती है। दरअसल, तीनों आरोपियों ने वीडियो नाबालिग के रिश्तेदार को भी दिखा दिया था। इसके बाद वह काफी डरी-सहमी रहने लगी थी। लेकिन बुधवार शाम उसने हिम्मत जुटाकर आपबीती अपनी मां को बताई और फिर तत्काल थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई। कोतवाली पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों का मेडिकल करवाया जा रहा है, उनके कागजात भी देखे जा रहे हैं। उनमें से दो नाबालिग हो सकते हैं। उनके पास से वह मोबाइल भी बरामद हुआ है, जिसमें वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। तीनों आरोपी पीड़िता के घर कस्बा क्षेत्र के रहने वाले हैं।

दावा- एक देश-एक चुनाव बिल कैबिनेट से मंजूर

नई दिल्ली (एजेंसी)। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक पैनल बनाया गया था। पैनल ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्रीय कैबिनेट से एक देश-एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी मिल गई है। न्यूज एजेंसी सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। इसमें कहा गया है कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा

संसद से बिल को चर्चा के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी।

सितंबर में सरकार ने इसके लिए बनाई गई हाईलेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने का प्रस्ताव था।

अविश्वास प्रस्ताव पर नड्डा बोले-ये चेयरमैन को चीयरलीडर कहते हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन गुरुवार को भाजपा ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा उठाया। भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को चीयरलीडर कहता है। उनकी मिमिक्री करता है। कांग्रेस बताती क्यों नहीं कि सोनिया-सोरेस का क्या कनेक्शन है। नड्डा के बोलने के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो बार उठकर बोलने की कोशिश की लेकिन वो बोल नहीं पाए। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

उधर, लोकसभा शुरू होते ही ऋ्रष्ट सांसद कल्याण बनर्जी के ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर हंगामा हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने कहा- बुधवार को सदन में जो कुछ हुआ, वह ठीक नहीं था।

मणिपुर सीएम बोले- हिंसा का जल्द स्थायी समाधान निकालेंगे

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मणिपुर हिंसा का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हालात नाजुक होने के कारण समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि म्यांमार के शरणार्थियों के यूनाइटेड नेशन्स की गाइडलाइन के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है।

सीएम बीरेन सिंह ने गुरुवार को कॉमरेड नुपी लान की याद में हो रहे एक कार्यक्रम में यह बात कही।

गडकरी बोले- वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में मुंह छिपाता हूं

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि जब भी मैं किसी अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाता हूं और वहां सड़क हादसों को लेकर बात होती है, तो मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूं। लोकसभा में सड़क हादसों पर चर्चा के दौरान गडकरी ने कहा कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है। स्वीडन रोड एक्सीडेंट

को जीरो पर ले आया है और भी बहुत से देशों ने इसे कम किया है। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैंने सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाला था, तो मैंने 2024 तक सड़क हादसों और इससे होने वाले मौतों को 50 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा था। एक्सीडेंट कम करना तो भूल जाइए, मुझे तो ये स्वीकार करने में भी कोई शर्म नहीं है कि ये बढ़ गए हैं। इसलिए किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सड़क हादसों पर चर्चा होने पर मैं मुंह छिपाने की कोशिश करता हूं।

जेएनयू में द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट% की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल हो गया। एबीवीपी ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी थी। इस दौरान कुछ छात्रों ने पथराव किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में लगाए गए फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए। एक छात्र ने मीडिया को बताया कि यह फिल्म एक तरफा कहानी दिखती है। इसमें ये दिखाया गया है कि गोधरा कांड के बाद क्या हुआ, लेकिन ये

नहीं दिखाया गया है कि पहले क्या हुआ था, जिसकी वजह से गोधरा जैसा हादसा हुआ।

दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 देगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने ?1000 रुपए देगी। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इस स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि योजना के लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव बाद महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम को बढ़ाकर ?2100 कर दिया जाएगा। 1. ऑटो चालक की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2. होली-दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए ढाई-ढाई हजार रुपए देंगे। 3. 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराया जाएगा। 4. ऑटो चालकों के बच्चों की कोचिंग का पैसा दिया जाएगा।

सोरोस और सोनिया के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है कांग्रेसः नड्डा

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा में सदन के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका के विवादास्पद निवेशक जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के संबंधों के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद श्री नड्डा ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि सदन में लोकतंत्र की मर्यादा का सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने समय-समय पर प्रजातांत्रिक प्रणालियों को ताक पर रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुंह से संसदीय प्रणालियों की चर्चा करना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि संसदीय प्रणालियों की बात करने वाली कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता संसद भवन परिसर में राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री की घटना की वीडियोग्राफी करते हैं और अन्य सदस्यों को इसके लिए उकसाते हैं। उन्होंने कहा,मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे कॉलेज के दिन याद आए। जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी के बाहर कॉलेज के लड़के जैसे करते हैं उसी तरीके की हरकत संसद के परिसर में नेता विपक्ष करते हैं और श्रीमती सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलती। उन्होंने कहा कि इससे संसदीय परंपराओं की मर्यादा गिरती है और संसदीय परंपराओं को चोट लगती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य श्रीमती गांधी और जॉर्ज सोरस के संबंधों के मुद्दे से ध्यान भटकाना है। उन्होंने कहा कि सब यह जानना चाहते हैं कि श्रीमती गांधी का ऐसे व्यक्ति से क्या संबंध है जो व्यक्ति हमारे देश को अस्थिर करना चाहता है और मुसीबत में डालना चाहता है। वह व्यक्ति भारत की संप्रभुता पर प्रश्न खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसकी कड़ी निंदा करता है और हम इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट बोला- मंदिर-मस्जिद विवादों पर आदेश न सुनाएं अदालतें

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में मंदिर-मस्जिद विवादों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर ना दें और न ही सर्वे के आदेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट (विशेष प्रावधानों) 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक्ट के खिलाफ सीपीआई-एम, इंडियन

मुस्लिम लीग, एनसीपी शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों ने याचिका लगाई है।

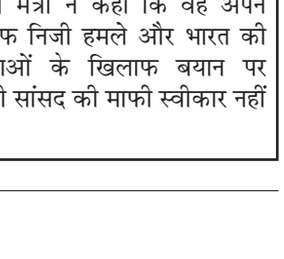

महाराष्ट्र परभणी हिंसा में 9 पुलिसकर्मी घायल, 50 उपद्रवी गिरफ्तार

परभणी (एजेंसी)। महाराष्ट्र के परभणी में हिंसा के बाद अब तक 8 मामले दर्ज किए गए हैं और 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नांदेड़ के शाहजी उमाप ने बताया कि हिंसा के दौरान एक सब इंस्पेक्टर समेत 9 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। तोड़-फोड़ में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में दो दिन के तनाव के बाद शांति है। शहर में बुधवार से ही आईपीएस की धारा 187 (आईपीएस की धारा 144 की तरह) लागू है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य रिजर्व पुलिस फोर्स की एक कंपनी बुलाई गई है। आईजी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसका इलाज चल रहा है। जांच के दौरान पता चला है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं घटना को ज्यादा तूल दिए बिना शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। मंगलवार को सोपन दत्तराव पवार (45) नाम के व्यक्ति ने परभणी रेलवे स्टेशन के सामने अंबेडकर स्मारक में संविधान की रेप्लिका तोड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, इसके बाद भी विरोध खत्म नहीं हुआ।

कल्याण बनर्जी के बयान से नाराज हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

नईदिल्ली(एजेंसी)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी द्वारा दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में की गई विवादास्पद टिप्पणियों की निंदा की और सदस्यों से अपने भाषणों में किसी भी जाति, समाज, महिलाओं या पुरुषों पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचने का अनुरोध किया। बिरला ने कहा कि कल सदन में जो कुछ भी हुआ वह अत्यंत अनुचित था और किसी भी सम्मानित सदस्य विशेषकर महिलाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। स्पीकर ने आगे कहा कि मैं सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने भाषणों में किसी भी जाति, समाज, महिला, पुरुष आदि पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से बचें। माननीय सदस्य (कल्याण बनर्जी) ने इसके लिए सदन में माफी भी मांगी है और मुझे लिखित में भी दिया है। लोकसभा में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद बनर्जी की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर की गई टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के सदस्यों के शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार बाधित होने के बाद तीसरी बार दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। बनर्जी ने सदन में 'आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024' पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्र सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान पश्चिम बंगाल की सरकार को मदद नहीं करने का आरोप लगाया था और जब

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सिंधिया ने उनकी बात का विरोध किया तो दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इसी बीच, बनर्जी ने सिंधिया के खिलाफ कोई टिप्पणी की और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस सदस्य के कुछ शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। बाद में बनर्जी ने अपनी टिप्पणी के लिए सिंधिया से माफी मांगी, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह अपने खिलाफ निजी हमले और भारत की महिलाओं के खिलाफ बयान पर विपक्षी सांसद की माफी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

गाबा की बारिश बढ़ाएगी भारत की टेंशन

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। जिसका तीसरा मुकाबला शनिवार 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाएगा। इससे पहले टेस्ट में भारत को बेहतरीन जीत मिली थी जबकि दूसरे टेस्ट में उसे हार झेलनी पड़ी। जिसके बाद सीरीज में अभी दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। वहीं दोनों की नजरें अब सीरीज में बढ़त बनाने पर होंगी लेकिन उससे पहले दोनों की अरमानों पर बारिश ने पानी फेर दिया है।

दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के पांचों दिन बारिश का संभावना है। वेदर फोरकास्ट के अनुसार, मैच के पहले दिन सबसे ज्यादा 88 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। जबकि दूसरे और चौथे दिन भी बारिश की होने के 40 प्रतिशत से अधिक चांसेस है। वहीं तीसरे दिन और पांचवें का पूर्वानुमान काफी बेहतर है, जिसमें 20 प्रतिशत के आसपास बारिश हो सकती है। जो खेल पर शायद ही असर डाले।

फैंस के जहन में अब ये सवाल है कि अगर गाबा टेस्ट बारिश की वजह से ड्रॉ होता है तो इसका भारत के डब्ल्यूटीसी फाइनल की रेस पर क्या असर पड़ेगा?

डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में भारत फिलहाल 57.29 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है। भारत के ऊपर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हैं जिनके अंक क्रमश- 63.33 और 60.71 प्रतिशत है। अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट ड्रॉ भी रहता है तो भी भारत डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंच सकता है।

भारत अगर गाबा टेस्ट ड्रॉ रहने केबाद अगले दो मुकाबले जीतता है और सीरीज 3-1 से अपने नाम करता है तो सीधा उन्हें फाइनल का टिकट मिल जाएगा। वहीं गाबा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भारत अगले दो में से एक मैच जीतता है और एक हारता है तो सीरीज 2-2 से समाप्त होगी। इस स्थिति में भारत को श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा। भारत को दुआ करनी होगी कि पड़ोसी टीम 1-0 से या फिर 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को हरा दे।

सिराज-हेड की तीखी नोकझोंक पर रिकी पोंटिंग ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था जिसे मेजबान टीम ने 10 विकेट से जीत लिया। इसके बाद पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। वहीं एडिलेड में हुए डे-नाइट टेस्ट के दूसरे दिन सिराज ने ट्रेविस हेड को 140 रन पर आउट करने के बाद उन्हें तीखा सेंड-ऑफ दिया था। इस घटना पर आईसीसी ने जांच के बाद दोनों खिलाड़ियों पर एक-एक डिमेरिट पॉइंट लगाया। वहीं इस मामले पर अब पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान रिकी पोंटिंग ने कहा कि, इस पूरे वाकये में मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में कोई द्वेष था। ये पूरी तरह से एक गलतफहमी का नतीजा था। उन्होंने बताया कि ट्रैविस हेड ने सिराज को आउट करने के बाद उनकी गेंद की सराहना की, लेकिन सिराज पिछली गेंद पर छक्का लगने से नराज थे। पोंटिंग ने आगे कहा कि, रोहित शर्मा अपने तेज गेंदबाजों से ऐसे ही जोश की उम्मीद करते हैं। जब उन्हें छक्का लगे और अगली गेंद पर विकेट मिले, तो प्रतिक्रिया स्वभाविक है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पोंटिंग ने सिराज को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जैसे ही सिराज ने हेड को सेंड-ऑफ दिया, मुझे चिंता हुई। अंपायर और मैच रेफरी इस तरह की चीजों को गंभीरता से लेते हैं।

भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये दो खिलाड़ी

नई दिल्ली (एजेंसी)। गूगल ने सबसे ज्यादा सर्च किए गए खिलाड़ियों और टीमों की लिस्ट जारी की है। आमतौर पर टॉप 10 में भारतीय क्रिकेटर्स का नाम शामिल होता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हालांकि, जो नाम टॉप 2 में मौजूद हैं उसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं हैं। बल्कि इस लिस्ट में टॉप पर पेरिस ओलंपिक 2024 से चर्चा में आई ट्रांसजेंडर बॉक्सर ईमान खालीफ है।

बता दें कि, टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। वहीं दुनिया में हार्दिक 7वें स्थान पर हैं। हार्दिक इस साल मुंबई इंडियंस के कप्तान बने थे। इस दौरान वह काफी चर्चा में रहे। इसके अलावा वह अपनी पत्नी नताशा स्टेनकोविक से भी अलग हो गए थे। जबकि टी20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पंड्या एक बार फिर सुर्खियों में छाए रहे।

जबकि इस लिस्ट में दूसरे भारतीय पंजाब किंग्स के शशांक सिंह हैं। आईपीएल ऑक्शन के दौरान शशांक सिंह के नाम पर काफी चर्चा हुई थी। ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने बोली लगाकर फिर ये दावा किया था कि उन्हें गलतफहमी हो गई। हालांकि, बाद में इसे नकार दिया।

2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सऊदी अरब को आधिकारिक तौर पर फीफा वर्ल्ड कप 2023 का मेजबान घोषित किया गया, जबकि 2030 का सीजन मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे भी शामिल होंगे। 2030 में वर्ल्ड कप के 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसका आयोजन 3 महाद्वीपों के 6 देशों में होगा।

2034 एशियाई खेलों के साथ-साथ 2027 एएफसी एशियाई कप के लिए मेजबान बनने के बाद सऊदी अरब को अब फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। अक्टूबर 2023 में फीफा ने 2034 वर्ल्ड कप की मेजबानी में रुचि व्यक्त करने के लिए देशों के लिए 25 दिन की समय सीमा तय की। इसमें ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब दोनों ने अपने नाम आगे बढ़ाए। ऑस्ट्रेलिया 2026 महिला एशियाई कप और 2029 फीफा क्लब वर्ल्ड कप की मेजबानी के अधिकार सुरक्षित करने के कुछ दिनों के बाद रेस से बाहर निकल गया। इससे सऊदी अरब एकमात्र उम्मीदवार रह गया। इसे फीफा ने भी समीक्षा में 5 में से 4.2 अंक दिए, जो कि 2026 के लिए अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को मिले अंक से ज्यादा हैं, जिन्हें 5 में से 4 अंक मिले थे। पिछले गुरुवार को सऊदी अरब अल नसर के लिए खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी सऊदी अरब का समर्थन करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया था।

बेकार गया स्मृति मंधाना का शतक, ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से भारत का सूपड़ा किया साफ

नई दिल्ली (एजेंसी)। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के शतक के बावजूद भारत को तीसरे और अंतिम महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में बुधवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 83 रन की हार के साथ 0-3 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। अरुंधति रेड्डी (26 रन पर चार विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से भारत ने वाका पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 78 रन कर दिया था लेकिन अनाबेल सदरलैंड (95 गेंद में 110 रन, नौ चौके, चार छक्के) के शतक से मेजबान टीम छह विकेट पर 298 रन का बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही।

सदरलैंड ने एशलेग गार्डनर (50) के साथ पांचवें विकेट के लिए 96 और कप्तान तहलिया मैकग्रा (56) के साथ छठे विकेट के लिए 122 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। इसके जवाब में भारतीय टीम मंधाना की 109 गेंद में 14 चौकों और एक छक्के से 105 रन की पारी के बावजूद 45.1 ओवर में 215 रन पर सिमट गई। जब तक स्मृति क्रीज पर थी तब तक भारत की जीत की उम्मीद बंधी हुई थी लेकिन उनके आउट होने के साथ मेहमान टीम की सांत्वना जीत दर्ज करने की उम्मीद भी

टूट गई।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऑफ स्पिनर एशलेग ने 30 रन देकर पांच विकेट चटकाए। लेग स्पिनर एलेना किंग ने भी 27 रन देकर दो विकेट हासिल किए। मंधाना को दूसरे छोर पर अन्य बल्लेबाजों से समर्थन नहीं मिला। एलेना ने हरलीन देओल (64 गेंद में 39 रन) को अपनी ही गेंद पर लपककर मंधाना के साथ उनकी दूसरे विकेट की 118 रन की साझेदारी का अंत किया जिसके बाद टीम ने लगातार विकेट गंवाए।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने पांचवें ओवर में ही रिचा घोष (02) का विकेट गंवा दिया जिन्हें मेगान शूट ने बोल्ड किया। टीम को कप्तान हरमनप्रीत कौर (22 गेंद में 12 रन) और जेमिमा रोड्रिग्ज (11 गेंद में 16 रन) से काफी उम्मीदें थी लेकिन इन दोनों ने निराश किया। सीनियर बल्लेबाज दीप्ति शर्मा भी खाता खोलने में नाकाम रहीं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद फोएबे लिचफील्ड (25) और जॉर्जिया वोल (26) ने पहले विकेट के लिए 10.1 ओवर में 58 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। अपना पांचवां एकदिवसीय खेल रही अरुंधति ने हालांकि 11वें ओवर में चार गेंद के भीतर दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को दोहरा झटका दिया। अरुंधति ने अंदर की ओर स्विंग होती गेंद पर पिछली मैच की शतकवीर वोल को बोल्ड किया जबकि बाएं हाथ की बल्लेबाज लिचफील्ड को बाहर की ओर स्विंग होती गेंद पर विकेटकीपर रिचा घोष के हाथों कैच कराया। अरुंधति ने इसके बाद ऑलराउंडर एलिस पैरी (04) को बोल्ड किया और फिर बेथ मूनी (10) को रिचा के हाथों कैच कराया जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट के 58 रन से चार विकेट पर 78 रन हो गया।

सदरलैंड और एशलेग ने इसके बाद पारी को संभाला। सदरलैंड ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने स्पिनरों को निशाने पर रखा और 40वें ओवर में दीप्ति शर्मा पर दो चौके और एक छक्का मारा। दीप्ति ने 34वें ओवर में एशलेग को मीनू मनि के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा। एशलेग ने 64 गेंद का सामना करते हुए पांच चौके मारे। सदरलैंड को इसके बाद कप्तान तहलिया के रूप में उम्दा जोड़ीदार मिली और दोनों ने तेजी से रन जुटाए तथा टीम का स्कोर 300 रन के करीब पहुंचाया। सदरलैंड ने पारी के अंतिम ओवर में दीप्ति पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़कर शतक पूरा किया लेकिन इसके बाद रन आउट हो गईं।

पाकिस्तान टेस्ट कोच जेसन गिलेस्पी का कटेगा पत्ता! पीसीबी ने कर दिया साफ

नई दिल्ली (एजेंसी)। टिम नीलसन की इस साल अगस्त में हाई-परफॉर्मेंस रेड-बॉल कोच बनाया गया था। उनके अनुबंध को पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद रिन्यू करना था। वो इसे लेकर निर्णय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ईएसपीएनक्रिकइन्फो को बताया कि उन्हें लगता है कि टीम के साथ अच्छी प्रगति कर रहे हैं और साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह प्रदिबद्ध हैं, लेकिन पीसीबी ने उन्हें बताया कि उनकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है।

वहीं माना जा रहा है कि पीसीबी ने गिलेस्पी को पहले से ये नहीं बताया कि अब वह साउथ अफ्रीका में बैगर सहायक कोच के होंगे। इस फैसले से वह बेहद नाखुश हैं। उनसे पहले से सलाह नहीं ली गई। ये उनकी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है। ये पिछले कुछ महीनों में गिलेस्पी की भूमिका और अधिकारों को सीमित करने का एक और उदाहरण है। अक्टूबर में उन्हें टेस्ट टीम के चयन पैनल से हटा दिया गया। उन्हें कहा गया कि अब वे केवल मैचडे स्ट्रेटजिस्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की सफेद गेंद की सीरीज के खत्म होने के बाद से खिलाड़ी और बोर्ड के बीच सीमित संवाद था। इस दौरे पर

गैरी कर्स्टन के जाने के बाद गिलेस्पी ने अंतरिम आधार पर टीम को कोचिंग दी थी।

गिलेस्पी को लगता है कि नीलसन ने खिलाड़ियों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाया है। ये बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई बार कही है। यही शायद उनके गुस्सा होने की वजह भी है। नीलसन को अनुबंध पाकिस्तान में नहीं रहने के कारण शायद नहीं बढ़ाया गया। ऐसा गिलेस्पी और नीलसन को लगता है।

फिलहाल, पीसीबी ने अभी तक नीलसन के रिप्लेसमेंट पर निर्णय नहीं लिया है। वर्तमान प्रशासन ने वर्ष की शुरुआत में नियुक्त विदेशी कोचों को पाकिस्तान के कोच से बदलना चाहता है। पीसीबी ने अतीत में विदेशी कोचों के प्रति अपनी अंसतुष्टि का कारण पाकिस्ता में पर्याप्त समय न बिताना बताया है।

खास तौर पर गैरी कर्स्टन के मामले में जिन्होंने अक्टूबर में पद छोड़ दिया था।

जो रूट बादशाहत खत्म

नई दिल्ली (एजेंसी)। टेस्ट क्रिकेट के फैब-4 में शामिल इंग्लैंड टेस्ट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रुट ने हाल ही में अपने हमवतन खिलाड़ी हैरी ब्रूक को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज करार दिया था। उनकी नजर में हैरी ब्रूक मौजूदा समय में विराट कोहली, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ से भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। जो की आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग से सच साबित हो गया है। दरअसल, हैरी ब्रूक ने जो रूट को बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में बादशाहत को खत्म कर दिया और खुद नंबर1 बल्लेबाज बन गए।

जो रूट लंबे समय से पहले स्थान पर मौजूद थे। हैरी ब्रूक ने 27 महीने पहले ही इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया और काफी कम समय में टेस्ट में नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं भारत के जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा गेंदबाजी और ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में टॉप पर कायम हैं। हैरी ब्रूक के अब 898 रेटिंग

पॉइंट्स हैं, जबकि जो रूट उनसे सिर्फ एक रेटिंग पीछे हैं। जो रूट के नाम 897 रेटिंग है। रूट इस साल जुलाई में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को पछाड़कर टॉप स्थान पर काबिज हुए थे और उन्होंने नौवीं बार टॉप स्थान हासिल किया था। हैरी ब्रूक ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। ब्रूक ने 23 टेस्ट मैचों में 61.62 की शानदार औसत और आठ शतकों के साथ 2280 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज ब्रूक ने 2024 में 11 टेस्ट मैचों में चार शतकों सहित 1099 रन बनाए हैं। ब्रूक ने सितंबर 2022 में इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू किया था।

बुमराह ने 890 रेटिंग अंकों के साथ टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप पर अपना स्थान बरकरार रखा है। उनके बाद साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा (856) और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड (851) का नंबर आता है। जडेजा ने भी 415 रेटिंग अंकों के साथ ऑलराउंडर्स की टेस्ट रैंकिंग में अपना टॉप स्थान बरकरार रखा है। बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज 285 अंकों के साथ इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं।

न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी का बड़ा खुलासा, कहा- भारत में मुझे मैच फिक्सिंग की दुनिया में धकेल दिया गया

नई दिल्ली (एजेंसी)। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज लू विंसेंट ने खुलासा किया है कि 2000 के दशक के आखिर में अब बंद कर दी गई इंडियन क्रिकेट लीग के दौरान वह मैच फिक्सिंग की दुनिया में कैसे आकर्षित हुए थे तथा वह एक गिरोह का हिस्सा थे जिसमें उन्हें अवसाद के दिनों में अपनेपन का एहसास होता था।

न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट और 108 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले विंसेंट पर 2104 में मैच फिक्सिंग के लिए इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आजीवन प्रतिबंध लगाया था। पिछले साल प्रतिबंध का दायरा कम करके उन्हें घरेलू क्रिकेट में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इस 46 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने करियर की शुरुआत 2000 के दशक की सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़कर की थी। इसके बाद हालांकि उन्हें अवसाद से

जूझना पड़ा और वह मैच फिक्सिंग की दुनिया में चले गए। इस तरह से उनका अंतरराष्ट्रीय करियर 29 साल की उम्र में समय से पहले खत्म हो गया। विंसेंट ने द टेलीग्राफ को दिए गए साक्षात्कार में बताया कि कैसे उनकी शुरुआती परवरिश ने उनके व्यक्तित्व और करियर को प्रभावित किया। उन्होंने कहा,'' मैं पेशेवर खिलाड़ी बनने के लिए मानसिक रूप से मजबूत नहीं था। इसलिए 28 साल की उम्र में मैं गहरे अवसाद में था और फिर भारत चला गया जहां मुझे मैच फिक्सिंग की दुनिया में धकेल दिया गया।''

विंसेंट ने कहा,''मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक गिरोह का हिस्सा हूं। इससे मुझे लगभग बेहतर महसूस हुआ, क्योंकि मैं सोच रहा था- मैं एक मैच फिक्सिंग गिरोह का हिस्सा हूं, मैं एक ऐसे समूह के साथ हूं जो मेरी पीठ थपथपाएगा और कोई भी हमारे बारे में नहीं जानता।'' पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होने के कारण विंसेंट हमेशा अपने आस-पास भावनात्मक समर्थन की तलाश में रहते थे और आखिरकार उन्हें वह सहारा भ्रष्टाचार की गंदी दुनिया में मिला।वह वर्तमान में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के संगठन की भ्रष्टाचार विरोधी शिक्षा पहल में शामिल हैं। उन्होंने कहा,'' मैंने 12 साल की उम्र से खुद का पालन पोषण किया और इसलिए मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों के बहकावे में आ जाता था।

मैं प्यार पाना चाहता था और इसलिए आसानी से भटक जाता था।''

विंसेंट को हालांकि मैच फिक्सिंग गिरोह का हिस्सा होने के खतरों का एहसास होने लगा था। उन्होंने कहा,''जब आप उस दुनिया का हिस्सा होते हैं तो फिर उससे बाहर निकलना आसान नहीं होता है।

राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को प्रदान किया स्वर्ण पदक और उपाधियाँ

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का बारहवां दीक्षांत समारोह रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल तथा कुलाधिपति मंगुभाई पटेल ने विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, पीएचडी तथा स्नातकोत्तर उपाधियाँ प्रदान की। समारोह में विख्यात समाजसेवी अच्युत सावंत को डी लिट् की मानद उपाधि प्रदान की गई। समारोह में विश्वविद्यालय की स्मारिका, दीक्षा पर्व तथा तीन अन्य पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल पटेल ने कहा कि सफेद बाघों की भूमि रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शिक्षा के नए प्रतिमान बना रहा है। विश्वविद्यालय में समाहित विन्ध्य के 9 जिलों के 240 कालेज उच्च शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को विकास के नए अवसर देने के साथ देश के विकास का भी मार्ग प्रशस्त कर रही है। नई नीति में जीवन मूल्यों से भरी भावी पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। राज्य पटेल शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। समारोह में राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में ज्ञान के साथ-साथ कौशल विकास और रोजगार मूलक प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ मानवीय मूल्यों का संरक्षण भी करें। अच्छे और सफल विद्यार्थी बनने के साथ-साथ जिम्मेदार नागरिक बनें। अपने माता-पिता और परिवार के अन्य बुजुर्गों की मन से सेवा करें। जिन्होंने आपको बनाने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित कर दिया उनकी किसी भी स्थिति में उपेक्षा न करें। राज्यपाल पटेल ने कहा कि अच्छा कॅरियर बनाकर हर विद्यार्थी अपने माता-पिता और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करे। वर्तमान जमाना नई सूचना तकनीक का है लेकिन इसके कई खतरे भी हैं। सोशल मीडिया का उपयोग केवल सकारात्मक कार्यों के लिए करें। आज इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराध हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए विद्यार्थी स्वयं जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें।

समारोह में कुलगुरू प्रोफेसर राजकुमार आचार्य ने विश्वविद्यालय की वर्ष भर की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को नेक में बी प्लस प्लस ग्रेड मिला है। विकास कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं जिससे ई लाईब्रोरी और डिजिटल लर्निंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में डिजी लॉकर में 11 लाख से अधिक अंकसूचियाँ रखकर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यहाँ के पाँच नवीन कार्यों को पेटेण्ट मिला है तथा तीन स्टार्टअप सफल कंपनी के रूप में कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में लोकपाल की भी नियुक्ति हो गई है। समारोह में शौर्य डोभाल ने कहा कि भारत का भविष्य विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थी तय करेंगे। यदि विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल है तो भारत का भी भविष्य उज्ज्वल बनेगा। भारत आज राजनैतिक और आर्थिक रूप से बहुत सशक्त है। भारत को विकसित करना है तो यहाँ के विश्वविद्यालयों के परिसरों को समृद्ध करना होगा।

समारोह में विख्यात समाजसेवी अच्युत सावंत ने कहा कि मैंने चार साल की आयु में अपने पिता को खो दिया। मुझे 12 वर्षों तक दो जून की रोटी और शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। मेरे मन में सदैव यही विचार और संकल्प रहा कि सफल बनने से अच्छा है सरल और अच्छा व्यक्ति बनना। मैंने पाँच हजार रुपए में एक छोटा सा संस्थान शुरू किया। आज भुवनेश्वर में कलिंगा विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज, स्कूल तथा कई अन्य संस्थान हैं जिनमें निःशुल्क आवासीय शिक्षा की व्यवस्था है। इन संस्थानों में लगभग एक लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे विश्वविद्यालय ने डी लिट् की मानद उपाधि देकर मेरे सामाजिक कार्यों को मान्यता देने के साथ मुझे गौरव प्रदान किया है। यह मेरी 63वीं मानद डी लिट् उपाधि है। मैं आप सब विद्यार्थियों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि चाहे जितना सफल बनें, चाहे जितना धन कमाएं लेकिन सदैव अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करें। रीवा का मेरे राज्य उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर से बहुत पुराना नाता है। रीवा के कई राजाओं ने मंदिर में दर्शन करने के साथ बहुमूल्य भेंटे दी हैं।

समारोह में 57 स्वर्ण पदक, 82 पीएचडी उपाधि तथा स्नातकोत्तर उपाधियों का वितरण किया गया। समारोह में प्रोफेसर नलिन दुबे द्वारा लिखी पुस्तक शिक्षा संस्कृति एवं नई दिशायें, डॉ संजय तिवारी द्वारा लिखी पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान एवं गांधीवादी विचारधारा तथा प्रोफेसर अतुल तिवारी द्वारा लिखी पुस्तक ग्लोबल रिसर्च फ्रंटियर जनरल का भी विमोचन किया गया। समारोह में कुलगुरू आचार्य ने अतिथियों को शॉल, फल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में विधायक मनगवां नरेन्द्र प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, कमिश्नर बीएस जामोद, आईजी एमएस सिकरवार, डीआईजी साकेत प्रकाश पाण्डेय, कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। समारोह का संचालन कुलसचिव सुरेन्द्र सिंह ने किया।

बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई यात्री बस, 2 की मौत, 6 घायल

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा के समान थाना क्षेत्र में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात युपी से गुजरात जा रही यात्री बस बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकरा गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 यात्री घायल हुए है। घायलों का रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश के प्रयागराज से सूरत होते हुए अहमदाबाद जाने वाली बस देर रात करीब 2 बजे समान ओवर ब्रिज पर ड्राइवर को नींद लगने से बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बस में सवार दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 यात्री घायल हो गए है। इसके स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। स्थानीय लोगों ने बताया कि डिवाइडर से टकराने के बाद बस रुक गई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा, हो सकता था। वहीं समान थाना प्रभारी ने विकास कपीस ने बताया कि, हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। मृतकों की पहचान की जा रही है। 6 लोग घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बनी हुई है।

राज्यपाल ने कैंसर की जाँच के लिये मैमोग्राफी मशीन का किया लोकार्पण

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल एक दिवसीय रीवा भ्रमण के दौरान संजय गांधी हास्पिटल का दौरा किया। राज्यपाल पटेल ने संजय गांधी हास्पिटल में स्तन कैंसर की जाँच के लिए लगाई गई मैमोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया। इसके बाद राज्यपाल ने सिकल सेल एनीमिया की जाँच के लिए बनाए गए बिरसा मुंडा सेंटर आफ एक्सीलेंस का भ्रमण किया। इस सेंटर में गर्भावस्था में गर्भ से नमूने लेकर सिकल सेल एनीमिया की जाँच की जाती है। राज्यपाल पटेल ने सेंटर में उपस्थित सिकल सेल से पीड़ित रोगियों तथा उनके परिजनों से भेंट की। राज्यपाल ने कहा कि नियमित उपचार से इस रोग पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त हो जाता है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि मध्यप्रदेश में सिकल सेल एनीमिया की जाँच और उपचार के लिए बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 86 लाख व्यक्तियों की जाँच में एक लाख 65 हजार व्यक्ति इस रोग के कैरियर पाए गए तथा 25 हजार से अधिक व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित पाए गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2047 तक सिकल सेल के पूरी तरह से उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे प्राप्त करने के लिए जन्म के 72 घण्टे के भीतर प्रत्येक शिशु की जाँच और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित पाए जाने पर पूरे उपचार की आवश्यकता है। साथ ही पूरे प्रदेश में लोगों को जागरूक करने के लिए गहन जागरूकता अभियान चलाएं। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ितों में लगभग 95 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं। विवाह से पहले वर-वधू की सिकल सेल एनीमिया की जाँच अवश्य कराएं। यदि दोनों इस रोग के कैरियर हैं तो उनका विवाह उचित नहीं होगा। लेकिन यदि कोई एक रोग का कैरियर है तो उनका विवाह हो सकता है। सिकल सेल को रोकने के लिए लगातार जाँच किया जाना आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने संजय गांधी हास्पिटल में बिरसा मुण्डा जाँच केन्द्र शुरू कराकर सराहनीय कार्य किया है।

समारोह में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं परियोजना प्रमुख डॉ बीनू सिंह ने सिकल सेल रोग के कारण, उपचार एवं बचाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संजय गांधी हास्पिटल का बिरसा मुण्डा जाँच केन्द्र प्रदेश का पहला जेनेटिक क्लीनिक है। साथ ही देश का प्रथम उत्कृष्टता केन्द्र है। कार्यक्रम में मेडिकल कालेज के डीन डॉ सुनील अग्रवाल ने उत्कृष्टता केन्द्र की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में विधायक मनगवां नरेन्द्र प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष मती नीता कोल, कमिश्नर बीएस जामोद, आईजी एमएस सिकरवार, डीआईजी साकेत प्रकाश पाण्डेय, कलेक्टर मती प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अधीक्षक संजय गांधी हास्पिटल डॉ राहुल मिश्रा, अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे।

सरकार के खजाने को लाखों की चपत लगा कर ओवरलोड मालवाहक वाहनों से कमाई कर रहे सरकारी नुमाइंदे

ओवरलोड मालवाहक वाहन सड़कों का कबाड़ा कर दुर्घटनाओं को भी दे रहे निमंत्रण

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जब से इस विभाग का जिम्मा अपने हाथों में लिया है तब से हर रोज कही न कहीं बेहतर और व्यवस्थित सड़कों का जाल बिछाने सरकारी प्रयास जारी है मगर इन सड़कों को लंबे समय तक सुव्यवस्थित तरीके से संजोकर रखा जाए इसकी जिम्मेदारी लेने वाला प्रशासनिक महकमा अपनी जबावदेहियों से मुंह मोड़ता हुआ दिखाई देता है जिसकी वजह से इन सड़कों में भारी और ओवरलोड वाहनों का संचालन तेज गति से होने लगता है जिसके कारण सड़कों के हालत बदतर हो जाते हैं और इनमें दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। रीवा में भी इन दिनों स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है जहां सड़कों के रखरखाव पर जिम्मेदारों के द्वारा चुप्पी साध ली गई है तथा यहां पर आए दिन भारी और ओवरलोड वाहनों का आवागवन हो रहा है परंतु इन वाहनों में कोई कार्यवाही करने की बजाय साहब लोग मलाई खाने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं अर्थात चलान के नाम पर अपने जेब का राजस्व बढ़ाते हुए दोबारा उसी वाहन को ओवरलोड कर चल की परमिशन देते जा रहे हैं।

दरअसल ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही की मुख्य जिम्मेदारी परिवहन विभाग यानी (आर टी ओ) की होती है परंतु कभी कभार पुलिस के आला अफसर भी अपनी रोटी सेंकने के लिए कार्यवाही पर जोर दे देते हैं जिसका असर मात्र इतना ही होता है कि (आरटीओ) विभाग के साथ ही यातायात और पुलिस को भी ओवरलोड कर सड़कों में चलने वाली वाहनों के मालिकों द्वारा सेट कर लिया जाता है और मोटी से मोटी रकम देकर अधिकारियों के मुंह बंद कर दिए जाते हैं जिसके बाद ओवरलोड माफिया सड़कों को दुरुस्त करने के काम में जुटकर अपने लिए आलिशान बंगलों तैयार करता है।

बताया जा रहा है कि रीवा में बालू, गिट्टी सहित खनिज और अन्य सामग्रियों को लेकर दिन में करीब सैकड़ा भर वाहन ओवरलोड होकर निकलते हैं जिनके द्वारा प्रति वाहन 3 हजार रुपए (आर टी ओ) 2 हजार रुपए प्रति थाना तथा 3- 3 हजार रुपए यातायात के साथ खनिज विभाग के रेट फिक्स किए गए हैं जिसके कारण धड़ल्ले के साथ ओवरलोड वाहनों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं जब किसी भी सरकारी विभागों में अधिकारियों की बदली होती तो उस वक्त अपना भय दिखाने और दाम बढ़ाने के लिए उक्त अफसरों द्वारा ओवरलोड पर नाम मात्र की कार्यवाही तो की जाती है मगर समय के साथ साथ व्यवस्था पुनः उसी पटरी में उतर कर दौड़ने लगती है।

आपको बता दें इन ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए शासन ने सड़क निर्माण के साथ ही टोल प्लाजा का संचालन भी शुरू किया है परंतु ओवरलोड माफिया यहां भी अपनी सेटिंग बनाकर चल रहा और जहां कांटा कराने के बाद 1 हजार और 15 सौ रुपए चार्ज होने चाहिए वहां बिना कांटा के ही टोल कर्मचारियों को प्रति वाहन 200 और 500 रुपए की राशि देकर शासन के खजाने में सेंध लगा रहा है तथा आम जनमानस की सुविधाओं को देखकर बनाने वाली सड़क को हादसे लायक सड़क बनाई जा रही है जिससे हर रोज हर पहर बस सड़क दुर्घटनाएं हो तथा कोई बेगुनाह काल के गाल में समाता जाए

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से 3 को मिली प्रोत्साहन राशि

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के वर या कन्या से अन्तर्जातीय विवाह करने वाले को दो लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के तहत दी जाती है। इस संबंध में जिला संयोजक जनजातीय कार्यविभाग ने बताया कि तीन व्यक्तियों को दो-दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। अशोक कुमार चौधरी निवासी ग्राम पटेहरा, मती अर्चना साकेत निवासी ग्राम खाम्हा तथा अमरजीत साकेत निवासी ग्राम बरों को दो-दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में जारी की गई है।

अल्पविराम परिचय कार्यशाला आज

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। शासकीय कर्मचारियों में आनंद की अनुभूति कराने एवं उनके दैनंदनीय कार्यों में सकारात्मकता के भाव में वृद्धि के उद्देश्य से जनपद स्तर पर अल्पविराम परिचय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। अपर कलेक्टर मती सपना त्रिपाठी ने बताया कि रीवा में 13 दिसम्बर को राज्य आनंद संस्थान भोपाल के सहयोग से प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभाग के 10-10 प्रतिभागियों तथा स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय, कृषि व जन अभियान परिषद के पाँच-पाँच शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों सहित प्रत्येक जनपद में 60 प्रतिभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री करेंगे 5175 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एक दिवसीय प्रवास पर 14 दिसम्बर को मऊगंज आएंगे। मुख्यमंत्री मऊगंज में कलेक्ट्रेट के समीप विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री समारोह में बच्चों को पोषण किट और छात्रवृत्ति का वितरण करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री मऊगंज जिले के विकास को गति देने के लिए 5175 करोड़ 39 लाख रुपए के कुल 57 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस संबंध में कलेक्टर मऊगंज अजय वास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री जी 54 निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसमें सीतापुर-हनुमना सूक्ष्म दबाव सिंचाई योजना लागत 5065 करोड़ रुपए शामिल है। इस परियोजना से पाँच साल में पूरे हनुमना क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसका मुख्य बाँध सीधी जिले में सोन नदी पर बनाया जाएगा। समारोह में 40 करोड़ रुपए की लागत से सिविल अस्पताल मऊगंज के 200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन तथा 24 करोड़ रुपए की लागत से 48 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण का भी शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री समारोह में 12 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से तीन निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज में 50 बिस्तर अस्पताल भवन का निर्माण लागत 5 करोड़ रुपए, हनुमना क्षेत्र में तिलया गांव में विद्युत सब स्टेशन निर्माण लागत 4.33 करोड़ रुपए तथा देवतालाब से तमरी मार्ग में ओड्डा नदी में पुल निर्माण लागत 3.51 करोड़ रुपए शामिल हैं।

जनकल्याण अभियान में शिविर तथा रैलियों का हो रहा आयोजन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। आमजनों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाए जाने तथा समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत जिले में शिविरों का सिलसिला जारी है। जनपद रायपुर कर्चुलियान अंतर्गत रामनई में ग्रामीणजनों द्वारा रैली का आयोजन कर लोगों को शिविर के लिए जागरूक किया गया। साथ ही शिविर में उपस्थित ग्रामीणजनों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। इसी प्रकार ग्रामीण स्तर पर रंगोली बनाकर भी आमजनों को शिविर के प्रति जागरूक किया गया। इसी तरह ग्राम पंचायत मझिगंवा, ग्राम पंचायत नीवा तथा ग्राम पंचायत सुरवार में भी जागरूकता रैली निकाली गई। जनकल्याण अभियान के तहत ग्राम पंचायत गगहरा, ग्राम पंचायत कपुरी में रंगोली बनाकर जागरूकता का संदेश दिया गया। इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि जिले भर में 15 दिसम्बर से जनकल्याण अभियान के शिविर लगाकर हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। शिविर के लिए तैनात नोडल अधिकारी तथा ग्राम स्तरीय दल 15 तारीख तक ग्राम पंचायतों में रैली निकालकर जनकल्याण अभियान की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार की जा रही है। इन हितग्राहियों को शिविरों में विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।

शहरी क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं जनकल्याण शिविर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। शासन के निर्देशों के अनुसार रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान 11 दिसम्बर से आरंभ हो गया है। अभियान के तहत विभिन्न नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन करके पात्र हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर मती प्रतिभा पाल ने बताया कि 12 दिसम्बर को नगर परिषद सेमरिया के वार्ड क्रमांक एक में हनुमान पार्क में शिविर लगाया गया। शिविर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में पार्षदगण तथा आमजन उपस्थित रहे। नगर परिषद गुढ़ के वार्ड क्रमांक एक में भी जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सीएमो केएन सिंह बघेल तथा वार्ड प्रभारी रामलखन साकेत द्वारा शासन की प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य योजनाओं के पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया। शिविर में आमजनता से पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई व्यवस्था तथा प्रकाश व्यवस्था के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण भी किया गया।

नेशनल लोक अदालत में 50 खण्डपीठों में होगी प्रकरणों की सुनवाई

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। प्रकरणों की सुनवाई के लिए 50 खण्डपीठें गठित की गयी हैं। इनमें पीठासीन अधिकारी तथा सहयोग देने के लिए सुलहकर्ता सदस्य तैनात किये गये हैं। जिला न्यायालय परिसर रीवा के साथ-साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मनगवां, मऊगंज एवं हनुमना में भी लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायालय में 29 खण्डपीठ, तहसील विधिक सेवा समिति मऊगंज में 7 खण्डपीठ, सिरमौर में 6 खण्डपीठ, त्योंथर में 5, मनगवां में एक खण्डपीठ एवं तहसील विधिक सेवा समिति हनुमना में 2 खण्डपीठ गठित की गयी हैं। लोक अदालत के दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति (क्लेम), 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भू-अर्जन, नगर पालिका निगम, प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे जायेगें।

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए खण्डपीठ क्रमांक एक में न्यायाधीश विक्रम सिंह, खण्डपीठ क्रमांक 2 में न्यायाधीश रमेश रंजन चौबे, खण्डपीठ क्रमांक 3 में न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह पाल, खण्डपीठ क्रमांक 4 में न्यायाधीश केशव सिंह, खण्डपीठ क्रमांक 5 में न्यायाधीश आनंद गौतम तथा खण्डपीठ क्रमांक 6 में न्यायाधीश प्रवीण पटेल को तैनात किया गया है। इसी तरह खण्डपीठ क्रमांक 7 में न्यायाधीश मती पदमा जाटव, खण्डपीठ क्रमांक 8 में न्यायाधीश दिलीप सिंह, खण्डपीठ क्रमांक 9 में न्यायाधीश संदीप वास्तव, खण्डपीठ क्रमांक 10 में न्यायाधीश शशांक खरे, खण्डपीठ क्रमांक 11 में न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी, खण्डपीठ क्रमांक 12 में न्यायाधीश मती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री, खण्डपीठ क्रमांक 13 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपसिंह कनेल, खण्डपीठ क्रमांक 14 में वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश देवदत्त प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।

इसी प्रकार खण्डपीठ 15 में वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश अक्षत तयाल, खण्डपीठ क्रमांक 16 में वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश पन्ना नागेश, खण्डपीठ क्रमांक 17 में वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश ललित कुमार मईड़ा, खण्डपीठ क्रमांक 18 में वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश सु अंजली अग्रवाल, खण्डपीठ क्रमांक 19 में कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश अमित सिंह धुर्वे, खण्डपीठ क्रमांक 20 में कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश सु अदिति अग्रवाल, खण्डपीठ क्रमांक 21 में कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश सु स्वाती रघुवंशी, खण्डपीठ क्रमांक 22 में कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश दिलीप महोर, खण्डपीठ क्रमांक 23 में कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश सु सृष्टि चौरसिया, खण्डपीठ क्रमांक 24 में कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश सु कंचन सैनिक, खण्डपीठ क्रमांक 25 में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रंजीत भड़करिया, खण्डपीठ क्रमांक 26 में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय शिवकांत, खण्डपीठ क्रमांक 27 मे अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम सुदीप कुमार वास्तव, खण्डपीठ क्रमांक 28 में औद्योगिक न्यायालय में न्यायाधीश केके मिश्रा तथा खण्डपीठ क्रमांक 29 में श्रम न्यायालय में न्यायाधीश अमित नगायच प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।

मऊगंज न्यायालय परिसर में खण्डपीठ क्रमांक 30 में न्यायाधीश संजीव कटारे, खण्डपीठ क्रमांक 31 में न्यायाधीश हीरालाल अलावा, खण्डपीठ क्रमांक 32 में न्यायाधीश साजिद मोहम्मद, खण्डपीठ क्रमांक 33 में न्यायाधीश मती गीता उइके, खण्डपीठ क्रमांक 34 मे न्यायाधीश आनंद बागरी, खण्डपीठ क्रमांक 35 में न्यायाधीश सु ओशी जैन, खण्डपीठ क्रमांक 36 में न्यायाधीश युवराज दीक्षित प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।

तहसील न्यायालय परिसर सिरमौर में खण्डपीठ क्रमांक 37 में न्यायाधीश संतोष चौहान, खण्डपीठ क्रमांक 38 में न्यायाधीश संजय वर्मा, खण्डपीठ क्रमांक 39 में न्यायिक मजिस्ट्रेट मती नेहा रहमान, खण्डपीठ क्रमांक 40 में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्तमश रहमान, खण्डपीठ क्रमांक 41 में न्यायिक मजिस्ट्रेट मती भारती केशरी कश्यप, खण्डपीठ क्रमांक 42 में न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।

तहसील न्यायालय परिसर त्योंथर में खण्डपीठ क्रमांक 43 में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दयाराम कुमरे, खण्डपीठ क्रमांक 44 में न्यायाधीश कमलेश मीणा, खण्डपीठ क्रमांक 45 में व्यवहार न्यायाधीश सु वंदना सोनी, खण्डपीठ क्रमांक 46 में न्यायाधीश मोहनी भदौरिया तथा खण्डपीठ क्रमांक 47 में न्यायाधीश आशुतोष प्रताप सिंह प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। तहसील न्यायालय परिसर हनुमना में खण्डपीठ क्रमांक 48 में न्यायाधीश विनोद कुमार चौधरी तथा खण्डपीठ 49 में न्यायाधीश मती कीर्ति दुबे तथा तहसील न्यायालय मनगवां में खण्डपीठ क्रमांक 50 में न्यायाधीश यश अबिद्रा प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक/प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया ऑडीटर पब्लिकेशन प्रा.लिमि. राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से प्रकाशित, **संपादक संदीप द्विवेदी**, आर.एन.आई नं. 69082/97, डाक पंजीयन क्र.- म. प्र./ रीवा संभाग/ 46/2023-2025, प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9589645803, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।